● वर्ष-4
● अंक-129
रायपुर, गुरुवार
09 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» नौकरी चाहिए तो...

11 से शुरु होगा भाजपा का संविधान गौरव अभियान

नारायण चंदेल बनाए गए अभियान संयोजक ,गुरु खुशवंत सह संयोजक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 11 जनवरी से 25 जनवरी तक भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा के परिप्रेक्ष्य में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी इस आयोजन की व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेशस्तरीय समिति भी गठित की गई है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने दी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री रोहरा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव के निर्देशानुसार च्च्संविधान गौरव सम्मान अभियानज्ज हेतु गठित प्रदेशस्तरीय समिति के संयोजक पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बनाए गए हैं। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब समिति के सह संयोजक होंगे और नीलकंठ टेकाम, अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय और श्रीमती किरण बघेल को सदस्य नियुक्त किया गया है। बुधवार को समिति की एक बैठक अभियान की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर हुई। कल 9 जनवरी को समिति की एक विस्तृत बैठक होगी जिसमें प्रदेश स्तर पर अभियान के सफल संचालन

की रूपरेखा पर चर्चा होगी। श्री रोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 26 नवम्बर, 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। सभी के लिए संविधान पवित्र एवं सर्वोच्च है, तब से प्रत्येक वर्ष संविधान के सम्मान में संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर संसद के दोनों सदनों में विगत माह व्यापक चर्चा हुई। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ0 बाबासाहब अम्बेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ के निर्माण के साथ-साथ अनेकों प्रेरणात्मक कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुए हैं। गरीब, शोषित एवं वंचित के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक कार्य निरंतर किये जा रहे हैं।

11 से 25 तक रखे जाएंगे विविध कार्यक्रम: चंदेल

संविधान गौरव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक नारायण चंदेल ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार देशभर में 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 11 जनवरी से 25 जनवरी तक सभी प्रदेशों की राजधानी एवं प्रमुख केन्द्रों पर 50 गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इन गोष्ठियों में केन्द्र सरकार के मंत्रीगण एवं भाजपा नेताओं का संबोधन होगा। इसी प्रकार सभी जिला केन्द्रों में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा च्हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमानज्ज पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय एवं सभी शिक्षण संस्थानों में च्हमारा संविधान हमारा स्वाभिमानज्ज विषय पर क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। युवा मोर्चा द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं कालेज संपर्क के माध्यम से युवाओं में भारत रत्न डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान और भाजपा की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रचारित किया जायेगा। श्री चंदेल ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल जिलों में रैली एवं सभा का आयोजन के अलावा 25 जनवरी को सभी मंडलों पर पार्टी के कार्यकर्ता आमजन के साथ एकत्रित होकर के भारतीय संविधान के प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे व संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे।

जेपीसी सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट

एक राष्ट्र-एक चुनाव पर पहली बैठक

नईदिल्ली। एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक में विपक्षी सदस्यों और भाजपा सांसदों ने कानून पर विचारों का आदान-प्रदान किया। 39-सदस्यीय जेपीसी की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों ने विधेयकों के प्रावधानों और उन्हें निर्देशित करने वाले औचित्य पर कानून और न्याय मंत्रालय की एक प्रस्तुति के बाद अपने विचार व्यक्त किए और सवाल पूछे। जहां भाजपा सांसदों ने विधेयकों को देश के लिए जरूरी बताया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे।

पहली बैठक के दौरान कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को राम नाथ कोविंद समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कथित तौर पर सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के प्रावधानों के बारे में भी बताया। बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संख्या पर सवाल उठाया।

बैठक के बाद समिति के सदस्यों को

एक बड़े सूटकेस में 18,000 पन्नों से अधिक दस्तावेज़ सौंपे गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सूटकेस के साथ एक तस्वीर शेयर की। सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, वन नेशन, वन इलेक्शन (ओएनओई) पर जेपीसी को हजारों पन्नों की एक रिपोर्ट मिली है। ओएनओई जेपीसी की पहली बैठक आज हुई। 18 दिसंबर, 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र द्वारा लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया गया था। फिर बिलों को समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। पैनल में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई विपक्षी सांसदों ने इस दावे पर सवाल उठाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से खर्च कम होगा। विपक्षी सांसदों ने यह भी

प्रियंका ने पूछा सवाल लगेंगी कितनी ईवीएम?

बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संख्या पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या एक साथ चुनाव आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा और एक बार में मतदान के लिए कितनी ईवीएम की आवश्यकता होगी। न्यूज18 के मुताबिक, प्रियंका ने दावा किया कि सरकार द्वारा बताए गए खर्च के आंकड़े 2004 में पहली बार ईवीएम लागू होने से पहले के हैं।

पूछा कि क्या 2004 के आम चुनावों के बाद कोई अनुमान लगाया गया था जब सभी 543 संसदीय सीटों पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसदों ने इस आरोप का प्रतिवाद किया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव ने कई राज्य विधानसभाओं को शीघ्र भंग करने और उनके कार्यकाल को लोकसभा के साथ लॉक करने की आवश्यकता करके संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।

बांग्लादेशियों के फर्जी प्रमाण पत्र, जांच के आदेश

नईदिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बुधवार को मालेगांव में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी किए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में भाजपा नेता किरीट सोमैया के आरोपों की एसआईटी जांच के आदेश दिए है। महाराष्ट्र गृह विभाग ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व नासिक के डीआइजी करेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी एसआईटी में होंगे। एसआईटी जांच कर समस्या पर अंकुश लगाने के उपायों के साथ रिपोर्ट देगी। 2 जनवरी

को, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मालेगांव के लगभग 1,000 लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे कहा कि नासिक कलेक्टर और नासिक नगर निगम ने मामले की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंन कहा कि मैंने पाया है कि एक घोटाला किया गया था जहां मालेगांव के लगभग 1,000 लोगों ने खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तहसीलदार से मुलाकात की और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अब नासिक कलेक्टर और नासिक नगर निगम ने मामले की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने एक संगठित आव्रजन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के बाद पांच अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और भारतीय पहचान हासिल करने में मदद करते थे, क्योंकि सहयोगियों ने उन्हें जाली आधार और मतदाता कार्ड जैसी भारतीय आईडी तैयार करने में मदद की थी। जांच से अवगत अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच अवैध प्रवासी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बरेली में रह रहे थे, जबकि सात भारतीय नागरिक दिल्ली और नोएडा के निवासी थे।

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी मा.नितिन नबीन का रायपुर विमानतल पर स्वागत मा.प्रदेश अध्यक्ष किरण देव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे,मंत्री केदार कश्यप ,भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा,भूपेंद्र सव्वनी,प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ,रायपुर जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर,रायपुर ग्रामीण श्याम नारंग सहित पदाधिकारीगण ने किया।

प्रमुख समाचार

माओवाद मामले में विल्सन-सुधीर धवले को जमानत

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को शोधकर्ता रोना विल्सन और कार्यकर्ता सुधीर धावले को जमानत दे दी, दोनों को 2018 में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस ए एस गडकरी और कमल खता की खंडपीठ ने उनके लंबे समय तक जेल में रहने और

मामले के जल्द निपटारे की संभावना कम होने पर यह निर्णय लिया। बचाव पक्ष के वकील मिहिर देसाई और सुदीप पासबोला ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी 2018 से जेल में हैं और अब तक विशेष अदालत में आरोप तय नहीं हुए हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस समय मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है। विल्सन और धावले को एक-एक लाख रुपये का मुचलका जमा करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर पीठ ने कहा कि मामले में 300 से ज़्यादा गवाह हैं और इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

माओवादियों के आत्मसमर्पण पर बीजेपी विधायक की चिंता

नईदिल्ली। कर्नाटक भाजपा के महासचिव सुनील कुमार ने छह माओवादियों के आत्मसमर्पण की सुविधा देने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर चिंता जताई है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने सरकार के कदम को वन नक्सलियों को शहरी नक्सली में बदलने के लिए बनाया गया

एक पैकेज करार दिया। यह आत्मसमर्पण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा माओवादियों से हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक मुख्यधारा में शामिल होने की अपील के एक सप्ताह बाद आया है। छह व्यक्तियों, मुंदगारू लता, सुंदरी कुथलूर, वनजाक्षी बालेहोल, मारेप्पा अरोली (कर्नाटक), के वसंत (तमिलनाडु) और जीशा (केरल) ने आज मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुमार ने सरकार की पुनर्वास नीति की आलोचना करते हुए उसके समय और मंशा पर सवाल उठाया। क्या सिद्धारमैया नक्सलियों के करीब हैं, या जो लोग नक्सलियों के करीबी हैं वे उनके करीब हैं? उन्होंने आरोप लगाते हुए पूछा कि यह नीति नक्सल विरोधी बल (एएनएफ) को हतोत्साहित कर सकती है, जो वर्षों से वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला कर रहा है।

लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था इंडि ब्लॉक: तेजस्वी यादव

बक्सर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य ही लोकसभा चुनाव था। यह पहले से ही तय था। बिहार के परिपेक्ष्य में बात करें तो यहां पर विपक्ष की सभी

पार्टियां शुरू से ही एकजुट है। हमलोग साथ में काम कर रहे। आगे भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजद के चुनाव लड़के के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह फैसला राष्ट्रीय जनता दल करेगा। अब तक हमारे दल ने इस पर फैसला नहीं किया है। पार्टी की स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने की संभावना है। दरअसल, तेजस्वी यादव बुधवार को बक्सर पहुंचे। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। राजद कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी यात्रा पर निकले हुए है। चार बार यात्रा का नाम बदल चुका है।

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से की सजा पर रोक लगाने की अपील

वॉशिंगटन। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि न्यूयॉर्क में गोपनीय भुगतान (हश मनी) मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा को रोक दिया जाए। ट्रंप के वकीलों ने बुधवार को शीर्ष कोर्ट का

रुख किया, क्योंकि न्यूयॉर्क के अदालतें सजा टालने की उनकी अपील को खारिज कर चुकी थीं। हश मनी मामले में सजा न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन तय करेंगे, जिन्होंने मई में ट्रंप को 34 आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया था। ट्रंप पर आरोप थे कि उन्होंने अपने व्यापारिक लेन-देन को छिपाने या गलत तरीके से दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजों में हेरफेर की। न्यायाधीश मर्चन ने यह संकेत दिया है कि वह ट्रंप को जेल की सजा, जुर्माना या परोल नहीं देंगे। ट्रंप के वकील सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दे रहे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। उनका कहना है कि इस फैसले के आधार पर ट्रंप के खिलाफ जो सबूत न्यूयॉर्क के हश-मनी मामले में इस्तेमाल हुए हैं।

महाभियोग के शिकार राष्ट्रपति येओल के समर्थक में वकीलों

सोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के वकीलों ने उनके खिलाफ मार्शल लॉ लागू करने के प्रयासों की निंदा की है। साथ ही देश के कार्यवाहक नेता ने राष्ट्रपति सुरक्षा कर्मियों और कानून प्रवर्तन एजेंटों के बीच टकराव की आशंका

जताई है। बता दें कि यून सुक येओलकी शक्तियों को 14 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था और अब संविधानिक न्यायालय इस पर विचार कर रहा है कि उन्हें पद से हटाया जाए या फिर बहाल किया जाए। पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां यून को हिरासत में लेने के लिए फिर से प्रयास कर रही हैं, जबकि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने उनके आवास को कंटीले तारों से घेर दिया है और उनके घर तक जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध किया है। यून पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को बार-बार सम्मन की अनदेखी की थी, जिसके बाद उनकी हिरासत की मांग की जा रही है। उनके वकीलों ने सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए नए हिरासत वारंट की वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि केवल अदालत की सुनवाई के बाद ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस, वैश्विक नेताओं से उलझ रहे एलन मस्क

कीर्तिवर्धन मिश्र

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बीते कुछ दिनों में राजनीति में जबरदस्त तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। खासकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद से। इस चुनाव के बाद एलन मस्क की ताकत किस हद तक बढ़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के विदेशी नेताओं से फोन कॉल पर बातचीत के दौरान मस्क के जुड़ने की भी खबरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं मस्क ने बीते कुछ दिनों में कई राष्ट्राध्यक्षों पर भी निशाना साधा है। उन पर देशों की अंदरूनी राजनीति में भी दखल देने के आरोप लगने लगे हैं।

गौरतलब है कि एलन मस्क ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था। इस पोस्ट में लिखा था- ट्रंप जीते, ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, कीएर स्टार्मर एक्सपोज हो गए, नाइब बुकेले ने अल साल्वाडोर में अपराध 95 फीसदी तक कम कर दिया। हाविएर मिलेई ने 2008 के बाद पहली बार अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर ले गए। महान व्यक्ति उभार पर हैं। हमें उनकी जरूरत होगी।

एलन मस्क पर मौजूदा समय में जिस देश की राजनीति में उलझने का आरोप लगा है, वह है ब्रिटेन। एलन मस्क ने बीते कुछ दिनों में ब्रिटेन की सत्तासीन लेबर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल का मुद्दा उठाया है। दरअसल, यहां पाकिस्तान से आए शरणार्थी, जो कि बाद में नागरिकता भी हासिल करने में सफल हो जाते हैं, पर ब्रिटिश लड़कियों को बहला-फुसलाकर गलत कामों में ढकेलने और उनके साथ यौन अपराध करने का आरोप लगा है। इसे लेकर ब्रिटेन में बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है।

एलन मस्क ने इसी मुद्दे पर कूदते हुए कीएर स्टार्मर और पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन का नाम लेकर उन पर यौन अपराधों में शामिल होने तक का दावा कर दिया। मस्क ने एक पोस्ट में तो यहां

तक आरोप लगाए कि गॉर्डन ब्राउन ने %पीड़ित छोटी बच्चियों को वोट के लिए बेच दिया।% इतना ही नहीं टेस्ला के मालिक ने 3 जनवरी को कहा था कि स्टार्मर ब्रिटेन के इस दुष्कर्म के अपराध में भागीदार हैं। उन्होंने मांग की कि स्टार्मर पर ब्रिटेन के इतिहास की इस सबसे खराब अपराध की घटना के लिए आरोप तय होने चाहिए।

मस्क के इन आरोपों का ब्रिटेन की सत्तासीन लेबर पार्टी के कई नेताओं और यहां तक कि पीएम कीएर स्टार्मर ने खुद जवाब दिया है। स्टार्मर ने कहा है कि कुछ लोग ब्रिटेन के बारे में झूठ और गलत जानकारियां फैला रहे हैं। वे पीड़ितों में कोई रुचि नहीं रखते, बल्कि वह सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हमें ऐसी डराने और हिंसा भड़काने से जुड़ी धमकियां पहले भी दे चुके हैं।

एलन मस्क ने बीते कुछ दिनों में जिन और देशों में अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है, उनमें जर्मनी भी शामिल है। दरअसल, जर्मनी में मौजूदा सेंटर-लेफ्ट सरकार के गिरने के बाद फरवरी में चुनाव तय किए गए हैं। एलन मस्क ने इसी मौके को लेकर जर्मनी में अति-दक्षिणपंथी पार्टी आल्टरनेटिव फॉर डायचेलैंड (एएफडी) का समर्थन कर दिया। मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट्स और जर्मनी के एक अखबार में ऑप-एड लेख तक लिखा था, जिसमें उन्होंने एएफडी का समर्थन किया था। माना जाता है कि यह पार्टी नाजी विचारधारा को बढ़ावा देती है। मस्क ने इस पार्टी के समर्थन में यहां तक कह दिया कि अब सिर्फ एएफडी ही जर्मनी को बचा सकती है।

इमैनुएल मैक्रों (फ्रांस)

अलग-अलग देशों के अंदरूनी मुद्दों में दखल देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एलन मस्क को घेरा है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि 10 साल पहले किसने ये सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया कंपनियों में से एक के मालिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी अभियानों का समर्थन करेंगे और जर्मनी समेत कई देशों के चुनावों में सीधे दखल देंगे। मैक्रों ने कहा है कि स्पेसएक्स के मालिक सीधे तौर जर्मनी समेत कुछ देशों के चुनाव में दखल दे रहे हैं।

जस्टिन ट्रुडो (कनाडा)

डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच टेस्ला के प्रमुख और अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर कटाक्ष किया था। उन्होंने आगामी कनाडाई संघीय चुनाव में उनके पतन की भविष्यवाणी तक कर दी थी। मस्क ने एक्स पर उस पोस्ट पर टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी की समाजवादी सरकार गिर गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था, %आने वाले चुनाव में ट्रूडो का खेल खत्म होगा।% इतना ही नहीं जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के प्रमुख और कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी मस्क ने एक्स पर लिखा- 2025 काफी अच्छा लग रहा है।

नॉर्वे के पीएम

इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा था कि वो यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में मस्क के हालिया बयानों से काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और सहयोगी देशों में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।

अमित अग्रवाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज है केस, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के आरोपी अमित अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित देश के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है। कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल के भाई अमित कुमार अग्रवाल को हवाला मामले में एसीबी ने 12 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया है। मामले में मई 2024 को ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज किया है। जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दिए आवेदन में कहा कि दर्ज एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

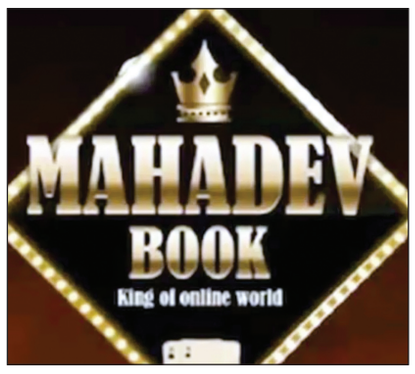

आवेदक का कहना है कि वह सह-अभियुक्त अनिल उर्फ अतुल का छोटा भाई है, जो महादेव बुक के संचालकों में से एक हैं और संबंधित है। वह वर्तमान में दुबई में रहकर काम कर रहे हैं। मामले में 145 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया जाना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसौदिया का उदाहर पेश कर जमानत दिए जाने की मांग की। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सट्टेबाजी ऐप का उपयोग किया गया है। वर्तमान आवेदक अपनी पत्नी के नाम पर सम्पत्ति खरीदा। आवेदक चतुर्भुज शर्मा को अलग-अलग तारीखों में 1.20 करोड़ रुपए का लेनदेन किया, जो उनके और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। अपने परिवार के सदस्यों के खातों में नकद जमा करना और प्राप्त करना बैंक प्रविष्टियां की गईं।

जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा, जांच के दौरान जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयान आवेदक के विरुद्ध आता है। कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार किया है।

हॉस्टल में प्रसव मामले में अधीक्षिका सस्पेंड

उठे कई गंभीर सवाल, हॉस्टल और प्रशासन की लापरवाही की कलई भी खुल चुकी

कोरबा। कोरबा के कन्या छात्रावास की अधीक्षिका जय कुमारी रात्रे को निलंबित कर दिया गया है। हॉस्टल में 17 साल की नाबालिग छात्रा के नवजात को जन्म देने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग को निर्देशित किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छात्रावास में रहकर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा प्रेग्नेंट हो गई। सोमवार रात करीब 2 बजे नाबालिग छात्रा का हॉस्टल में ही प्रसव हुआ और रात में ही नवजात जीवित बच्चे को हॉस्टल के पीछे फेंक दिया गया। अब तक की जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा ने ही बात छिपाने के लिए ऐसा किया था।

इस पूरे मामले में छात्रावास अधीक्षिका ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे छात्रा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी हुई तो उससे पूछा गया, उसने दस्त की शिकायत बताया लेकिन लक्षण लगे नहीं। माहवारी सम्बन्धी बात पूछने पर होना बताया, तब उसे अस्पताल चलने के लिए कहा गया। इस बीच हॉस्टल परिसर

से बच्चे के रोने की आवाज आने पर स्टाफ ने तलाश किया, तो परिसर में टॉयलेट के पीछे नवजात शिशु मिला। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि छात्रा का प्रसव हुआ है।इस मामले में हॉस्टल की अधिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है।

कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया हॉस्टल में नवजात की डिलीवरी मामले के संज्ञान में आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है।इसके साथ ही कार्य में लापरवाही पाए जाने पर हॉस्टल की अधीक्षिका को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। आगे जिस तरह की जानकारी सामने आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हॉस्टल में पैदा हुई नवजात बच्ची का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। उसे एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। क्योंकि बच्ची को खिड़की के बाहर फेंका गया था। काफी देर खुले वातावरण में रहने से ठंड के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। शरीर पर खरोच के भी निशान हैं। जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ राकेश वर्मा ने कहा कि बच्ची की हालत अभी गंभीर है। 5 से 7 दिन तक उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ेगा। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

इस घटना के बाद हॉस्टल और प्रशासन की लापरवाही की कलई भी खुल चुकी है। ट्राइबल जिला होने के कारण छात्रावास में ज्यादातर बच्चे आदिवासी इलाके से ही आते हैं। नियमों के अनुसार नियमित अंतरालों पर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। अधीक्षिका को हॉस्टल में ही निवासरत रहना चाहिए, बाहर के किसी व्यक्ति का हॉस्टल में जाना प्रतिबंधित है। लेकिन इस मामले के संज्ञान में आने के बाद बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्कूल में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रहने वाली छात्रा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो हॉस्टल में ही बच्चे को जन्म दे देती है और इसके बाद अधीक्षिका को इस बात की जानकारी हुई। नाबालिग प्रेग्नेंट कैसे हुई? पैदा होने वाले नवजात का पिता कौन है? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

कन्हर नदी पर तेजी से चल रहा पुल का काम

कई गांवों को मिलेगी राहत, बारहों महीने निर्बाध आवागमन की मिलेगी सुविधा

बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोडऩे कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप

मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम अगले साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढऩे के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।

पुल के निर्माण से ये 20 गांव होंगे लाभान्वित

धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी।

पीएम सूर्यघर योजना : अब तक आए जिले में 540 आवेदन

सूर्य की किरण से 1000 घर होंगे रोशन, बेच भी सकेंगे बिजली

जांजगीर-चांपा। जिलेवासी अब बिजली की भारी बचत व आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए पीएम सूर्य मुत योजना के तहत आवेदन कर मकान में सोलर पैनल लगाना होगा। इसमें बिजली की बचत के साथ आप विभाग को बिजली बेच भी सकेंगे। इसके तहत जिले में 1 हजार का लक्ष्य मिला हुआ है। अब तक 540 लोगों का आवेदन भी आ चुका है। साथ ही अब 22 लोग अपने मकानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवा भी चुके हैं। पीएम घर मुत सूर्य योजना के तहत बिजली विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य मिला हुआ है। इसके तहत जिले में बिजली विभाग द्वारा लगातार शिविर लगाकर योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले में अब तक 540 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया होने के साथ ही संबंधित वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है। अब तक जिले में 22 घरों में योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जा चुका है। जिले में 1000 का लक्ष्य मिला हुआ है।

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस आनलाइन है। जिससे घर बैठे उपभोक्ता इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इसे लगाने के लिए लोन की सुविधा भी दी जा रही है। जिससे उपभोक्ता इसका लाभ सब्सिडी के तौर में ले सकता है। अगर घर में सोलर पैनल लगते ही बिजली की भारी बचत होगी। साथ ही बिजली को विभाग को बेच सकेंगे। आय में भी वृद्धि होगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अकलतरा संभाग में प्रथम सोलर इंस्टालेशन किया गया। साथ ही इसके तहत 3 जनवरी को नरियरा व तिलई में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक संया में सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

78 हजार तक मिलेगी सब्सिडी

पीएम घर सूर्य मुत योजना के तहत आवेदन करने के लिए एक माह अंतर्गत काम शुरू हो जाएगा। 1 से 2 किलो वॉट क 30 हजार से 60 हजार रुपए, 2 से 3 किलो वॉट तक 60 हजार से 78 हजार रुपए, 3 किलो वॉट से अधिक 78 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल लगाने की अनुमति घर के खपत के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

सोलर पैनल लगाने इस तरह कर सकते हैं आवेदन

केन्द्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल लांच किया है। इसके लिए आप बेससाइट पीए सूर्यघर डॉट जी ओव्हीडॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसमें आपको अपने बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर, नाम, पता राज्य और कितनी क्षमता का प्लांट लगाना जानकारियां भरनी होगी। उसी के अनुसार यहा सोलर पैनल लगेगा और सब्सिडी मिल पाएगी। बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सत्यापित करेंगे। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पोर्टल पर कई वेंडर पंजीकृत हैं, जो सोलर पैनल लगाते है। अपने हिसाब से वेंडर चुन सकते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बलिदान हुए सुदर्शन को दो माह के मासूम ने दी अंतिम विदाई

दंतेवाड़ा। बीजापुर जिले के कुटरू इलाके में नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए आईईडी विस्फोट किया था जिसमें आठ जवान बलिदान हुए थे। इस हादसे में एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। यह घटना उस समय हुई जब डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस भीषण हमले में मौके पर ही सभी जवान बलिदान हो गए जिनमें वाहन चालक भी शामिल था। घटना इतनी भयावह थी कि शहीद जवानों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में शहीद हुए सभी जवानों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सलामी के साथ उनकी शहादत को नमन किया गया और यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा ली गई कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दौरान मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला सामने आया, जहां शहीद जवान सुदर्शन वेट्टी के अंतिम संस्कार में उनके दो महीने के मासूम बेटे ने पिता को अंतिम विदाई दी। इस दौरान मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थीं। हर कोई गमगीन था।

साइबर ठगों ने लोगों के खातों से निकाले लाखों रुपये

दुर्ग। दुर्ग जिले में इस बार साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सैकड़ों की संख्या में अवैध रुप से लाखों रुपए खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी पुलिस को गृह मंत्रालय के पोर्टल से मिली। पुलिस शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित कर्नाटका बैंक के 111 खाता धारकों के अकाउंट में अलग-अलग राज्यों में हुए साइबर ठगी द्वारा अर्जित 86 लाख 33 हजार, 247 रुपए पाए गए हैं। उक्त 111 बैंक खातों में अवैध रुप से लाभ अर्जित करने के लिए खातों का उपयोग किया गया है। इन खातों को लेकर अन्य राज्यों में ऑन लाइन शिकायत भी दर्ज की गई है। इसे लेकर साइबर क्राइम की टीम खातों के लेने देन को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी खाता धारक का नामजद कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में पुलिस खाता धारकों के आधार कार्ड समेत उनका डिटेल मंगाकर पूछताछ करेगी।

धान खरीदी केंद्र में 6768 बोरा फर्जी खरीदी का मामला उजागर

रायपुर। राजनादगांव जिले में धान उपार्जन केंद्रों में तेजी से चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के बीच रामपुर धान खरीदी केंद्र पर बड़ी अनियमितता सामने आई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत स्थित इस केंद्र का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण में सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामपुर द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र में लगभग 6768 बोरा धान प्रथम दृष्टया फर्जी खरीदी किया पाया गया। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी दिलीप चंद्राकर और ऑपरेटर नरेन्द्र वर्मा मौके पर उपस्थित थे। कलेक्टर अग्रवाल ने इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों का संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

बाइक चोरी के आरोपी को दो वर्ष सश्रम करावास की सजा

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन में खड़ी बजाज विक्रांत बाइक की चोरी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रे को 2 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है वही अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है। सहायक लोक अभियोजन एस.अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक गंगाधर क्रश जोकि 21 नवंबर 2019 को सुबह करीबन 9 से 10 बजे ड्यूटी पर आया हुआ था और बाइक को बजाज विक्रांत सीजी 11 एके 2179 को पुलिस लाइन मैदान में रखा हुआ था। जब 1.30 बजे करीबन बाहर आया तो बाइक नहीं मिला, आस पास खोजने पर भी कुछ पता नहीं चलने पर सिटी कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। इस दौरान जांच पड़ताल शुरू की गई, बाइक की चोरी के संदेह में पूछताछ के बाद पता चला कि पुलिस लाइन में ही पदस्थ राकेश रात्रे ने ही बाइक की चोरी की थी। जिसके कब्जे से बरामद कर विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया गया।

जातिगत गाली-गलौच करने पर भाजपा नेत्री पहुंची जेल

सारंगढ़ (बिलाईगढ़)। जातिगत गाली-गलौच करते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद आखिरकार भाजपा नेत्री हेमकुँवर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। नगर में यही चर्चा थी कि एक तरफ जिला भाजपा अध्यक्ष ज्योति पटेल के नाम की घोषणा होने पर भाजपाई खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेत्री हेमकुँवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया। दरअसल, चंद रोज पहले भाजपा नेत्री हेमकुँवर अपने क्षेत्र के कार्यों को लेकर जनपद पंचायत पहुंची थी। जहां उनका जनपद कर्मचारी नारद से किसी बात को लेकर तूतू, मै-मै हो गया। दोनों के बीच कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि मामला गाली-गलौच तक जा पहुंचा। वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री घटना के लिए उकसाते सुनाई और दिखाई पड़ रहा है। मामले में जनपद पंचायत के कर्मचारी नारद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच उपरांत पुलिस ने महिला भाजपा नेत्री हेमकुँवर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कर दिया। फिलहाल, मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हिराडबरी के निवासियों के लिए संजीवनी साबित हुआ जल जीवन मिशन

पेयजल के लिए ना तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और न ही इंतजार, महिलाओं की मुश्किलें हुई दूर

सूरजपुर। पेयजल मनुष्य की बुनियादी और सर्वप्रमुख आवश्यकता में से एक है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र के बहुत बड़े वर्ग को पेयजल एवं निस्तारी हेतु पानी की उपलब्धता के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां की बड़ी जनसंख्या को आज भी समुचित मात्रा में पेयजल सुनिश्चित नही हो पा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत देश के हर घर में नल कनेक्शन प्रदाय कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु कार्य किया जा रहा है। यह योजना देश लोगों के स्वास्थ्य उन्नयन के लिए कारगर योजना साबित हो रहा है।

जिले के विकासखण्ड-सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत-सम्बलपुर के ग्राम हिराडबरी के ग्रामीणों को पेयजल एवं निस्तारी हेतु समुचित मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से आज यह योजना ग्रामवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के शुरू होने के पूर्व ग्राम हिराडबरी के ग्रामीणों को दूर जाकर पानी का प्रबंध करना पड़ता था। पूर्व में ग्रामीण पीने के पानी के लिए कुएँ पर निर्भर थे जिसमें गर्मीयों के मौसम में जल स्तर कम होने से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था तथा बरसात आने पे कुएँ में मटमैला पानी भर जाता है। जिसमें पीने का पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी।

परन्तु आज इस योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्राम की

महिलाओं को काफी सुविधा हो रही है। ग्रामीण महिलाएं को पानी के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता था जिसके कारण उन्हें समय पर अपने घरेलु जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कठिनाई होती थी। आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम के सभी घरों में नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल एवं निस्तारी हेतु समुचित मात्रा में पानी की प्रबंध के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नही हो रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना से अब पानी सुबह शाम दो समय घरों तक उपलब्ध होता है। जिससे ग्रामवासी बहुत खुश और लाभान्वित नजर आये। इस योजना की सराहना करते हुए ग्राम के लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से इस योजना के फलस्वरूप हम ग्रामीणों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे सेहत की सुरक्षा के साथ-साथ समय की भी बचत हो रही है। अब हम घरेलु एवं अन्य जरूरी कार्यों को समय पर कर पा रहे हैं। अब ग्रामीण सुखद भविष्य के लिए पूरी तरह से आशान्वित होकर जल संकट की समस्या से भी मुक्त हुए हैं। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि जिले के विकासखण्ड -सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत-सम्बलपुर के ग्राम हिराडबरी में भारत सरकार की महत्वकांक्षा योजना जल जीवन मिशन योजना के तहत लागत कुल रु. 57.56 लाख 06 नग 5000 लीटर सोलर आधारित योजना द्वारा समस्त ग्राम के 89 घरों में जल प्रदाय किया जा रहा है। हिराडबरी ग्राम पंचायत सम्बलपुर, का आश्रित गॉव है। जिसमें लगभग 89 परिवार निवासरत है। जिसमें सभी परिवार में नल कनेक्शन लगा गया है जिसमें एक पानी टंकी के माध्यम से 89 घरों तक शुध्द पेयजल सप्लाई किया जा रहा है।

जमींदोज हुआ बिलासपुर का मिशन अस्पताल

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लीज के चर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर आज मिशनरी कब्जे के अस्पताल को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर निगम अमला 10 बुलडोजर के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने जुट गया है। कैम्पस के भीतर बने भवनों को ढहाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी 30 सालों तक प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया। साथ ही शर्तों का उल्लंघन करते हुए डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ाकर लाखों रुपए की कमाई करने लगे। कैम्पस के भीतर एक रेस्टोरेंट भी इस पर संचालित हो रहा था। कलेक्टर अवनीश शरण ने मिशन हॉस्पिटल के लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर दस्तावेजों की पड़ताल करने का निर्देश दिया। जांच में पता चला कि 31 अप्रैल 1994 तक लीज की अवधि थी और सेवा के नाम पर लीज लेकर व्यवासायिक उपयोग करने लगे और लाखों रुपये किराए भी वसूल करने लगे थे। जांच के दौरान यह मालूम पड़ा कि 92069 वर्ग फिट अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय भी किया गया था। बिलासपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने मामले में सुनवाई की। जिसमें पूर्व कमिश्नर के स्टे के आदेश को खारिज कर दिया था। जिसके बाद जिला प्रशासन और निगम बुधवार को अस्पताल भवन को जमीदोज करने की कार्रवाई में जुट गया है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से परिवीक्षाधीन वन सेवा के अधिकारियों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से बुधवार को

राजभवन में भारतीय वन सेवा के 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। डेका ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया। डेका ने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी व अनुशासन के साथ करें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की समझाइश दी और कहा कि वनों की सुरक्षा और संरक्षण व देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्य को अपना प्रथम कर्तव्य मानना चाहिए। राज्यपाल ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को अपने कार्य में नवाचार करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रभारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नवीद शजाउद्दीन तथा वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी सु श्वेता कम्बोज, तन्मय कौशिक , गौतम पदीभर और सुमेध संजय सुरवाडे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव

साय से सीएम हाउस में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने शाल-फल भेंटकर सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सद्गुरु से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धर्मांतरण पर बनेगा नया कानून, प्रदेश में धर्म परिवर्तन करना नहीं होगा आसान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाने जा रही है। इसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कई अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य में धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाने जा रही है। इससे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थम सकते हैं। बता दें कि वर्तमान समय में राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए किसी तरह की कानून नहीं बने गई है। अब राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग अभी विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण के संबंध में बनाए गए नियम कानून का अध्ययन कर रहा है। जिन राज्यों में बेहतर कानून है, उसके प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, आठ से दस राज्यों की कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

राज्यपाल डेका से डॉ. सी.व्ही. रमन विवि के कुलाधिपति ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ अरूण आर जोशी ने सौजन्य भेंट की। डेका ने यू.सी.जी के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अरविंद तिवारी सहित डा. नितिन वत्स व डॉ. उषा किरण अग्रवाल उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को मिला केबिनेट मंत्री का दर्जा

रायपुर। राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज, को राज्य सरकार ने केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। डॉ. सलीम राज ने केबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

राज्यपाल डेका से रेल्वे अधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश और संभागीय रेलवे प्रबंधक रायपुर दयानंद ने सौजन्य भेंट की।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव: छत्तीसगढ़ के 75 युवा दिल्ली में दिखाएंगे अपना टैलेंट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले- मनमोहक प्रस्तुति से युवा प्रदेश का नाम करें रोशन

रायपुर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने जा रहे युवाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। भारत मण्डपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विज़न को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने कहा कि युवा दिल्ली में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आगामी 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ऐसा प्रदर्शन करें कि देश के अन्य राज्यो से आये युवाओं के जुबान पर छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया हो।

खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे।

गौरतलब है कि युवा महोत्सव के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डॉयलाग सम्पन्न हुआ। भारत को विकसित बनाने के लिए भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, महिलाओं को सशक्त बनाना और सामाजिक संकेतक में सुधार, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, भारत को एक स्पोर्टिंग और फिट राष्ट्र बनाना, भारत को वैश्विक विनिर्माण पावर हाऊस बनाना, भारत को विश्व की स्टार्टअप राजधानी के रूप में विकसित करना, भारत को पूर्णत: टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना, विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकास भी विरासत भी की थीम पर माई भारत पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख 26 हजार से अधिक पंजीकृत वालेंटियर्स एवं प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए सर्व प्रथम आनलाइन क्वीज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन क्वीज़ में क्वालीफाईड 6,103 युवाओं में से 635 युवाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी निर्धारित 10 थीम पर निबंध लेखन किया। निबंध लेखन अंतर्गत प्रत्येक विषय में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया जाना था। इसमें से 228 युवाओं का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया गया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी ई। रोड रायपुर में स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत युवा प्रतिभागियों ने पी ।पी ।टी। के माध्यम से भारत को विकसित बनाने हेतु अपना विज़न विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ राज्य से 12 विषय विशेषज्ञों ने युवा प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत विज़न पी ।पी ।टी। का मूल्यांकन किया।

स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन कर उन्हें नई दिल्ली भेजने के लिए ऋस्द्गठ्ठस्त्रद्बठ्ठद्द ह्द्बद्धऋ समारोह का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो अवलोकन कर राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन लोकगीत, लोकनृत्य, कविता, कहानी, चित्रकला, साइंस मेला एवं वक्तृत्व कला विधाओं से चयनित किया गया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायकगण किरण देव, मोतीलाल साहू, इंद्र कुमार साव, अनुज शर्मा,गुरु खुशवंत साहेब, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता और संचालक तनुजा सलाम सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और युवा उपस्थित थे।

सीएम ने दी 268 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमतापूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह में उक्त बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने 268 करोड़ रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामित्व कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों की बड़ी समस्या आज दूर हो रही है। इन लोगों को आबादी भूमि पर स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिल रहे है। दस्तावेज नहीं होने के कारण अक्सर विवाद की स्थिति में मामले न्यायालयों में सालों-साल लंबित रहते थे। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या को समझा और उसे दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को तकनीक दृष्टि से सक्षम होना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। रजिस्ट्री में लोगों को आसानी हो, यह पारदर्शी प्रक्रिया से हो, इसके लिए हमने सुगम एप तैयार किया है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के लिए जो ड्रोन सर्वे हमने कराये, इससे आबादी भूमि का अद्यतन नक्शा हमारे पास तैयार हो गया है, इसके कई लाभ हमें मिलेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत की विकास योजना अर्थात जीपीडीपी बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। इससे शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने में काफी मदद मिलेगी और अतिक्रमण की संभावना समाप्त होंगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यह सोचा कि कमार बसाहटों तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए, इनके लिए भी साफ पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। जब ऐसी संवेदनशीलता मन में होती है तभी पीएमजनमन जैसी योजना अस्तित्व में आती है। एक साल के भीतर प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजाति की बसाहटों में विकास का उजाला फैला है। लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 36 सड़कें हमने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास, सौभाग्य योजना, जलजीवन मिशन, पीएम जनमन योजना सारी योजनाएं नागरिकों के जीवन को आसान करती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की राह खोलती हैं।

महापौर की सीट महिला के लिए आरक्षित होते ही दावेदारों में लगी होड़

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस में दावेदारी की रेस शुरू हो चुकी है। रायपुर नगर निगम में महापौर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है ऐसे में दोनों ही पार्टियों की नेत्रियां खुलकर पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी रख रही है। इनमें कुछ नाम कुछ नाम खुलकर सामने आए है वही कुछ नामों की संगठन में चर्चा तेज हो चुकी है।

मीनल चौबे- निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सक्रियता से निभायी है। संगठन की राजनीति में सक्रिय हैं। सामान्य महिला में इनकी दावेदारी सबसे मज़बूत मानी जा रही है। **शैलेंद्री परगनिहा**- संगठन में शैलेंद्री परगनिहा का नाम चर्चे में है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य है। 25 साल से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय है। संगठन में पार्षद, ज़िलाध्यक्ष, महामंत्री जैसे अहम भूमिका में रही है। दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा है कि टिकट के लिए मज़बूत दावेदारी है, पार्टी ने मौक़ा दिया तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और जिसे भी टिकट मिलेगी उनके लिए डटकर काम करेंगे। **वर्णिका शर्मा**- संगठन में सक्रिय है। संगठन के मुद्दों को प्रमुखता से रखती आई हैं। पार्टी में वर्णिका शर्मा का नाम भी चर्चे में है। संघ से जुड़ी वर्णिका शर्मा नक्सल विषयों पर मुखर रही हैं। संगठन में इनके नाम की चर्चा है। हालाँकि, इन्हें इसकी जानकारी अब तक नहीं है। **शताब्दी पांडेय**- संगठन और संघ से जुड़ी हुई है। छात्र राजनीति से सक्रिय है, कई अहम भूमिका में रही है। शताब्दी पांडेय का भी नाम सुर्ख़ियों में है, बातचीत में उन्होंने महापौर के टिकट की स्वाभाविक दावेदारी पेश की है और कहा है कि संघ और संगठन जो ज़िम्मेदारी देगी उसे निभायेंगे। **प्रभा दुबे**-संगठन की राजनीति में सक्रिय है। प्रभा दुबे को पार्टी ने किरणमई नायक के मुकाबले महापौर प्रत्याशी बनाया था, उनको हार का सामना करना पड़ा था। सक्रिय चेहरों और चर्चे में इनका नाम भी शामिल है। **सीमा संतोष साहू**- दो बार पार्षद के तौर पर चुनी गई है और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। ओबीसी वर्ग से आती हैं। महापौर की टिकट के लिए दावेदारी भी कर रही है। **सरिता दुबे**-ब्राह्मण पारा से पार्षद है। निगम की राजनीति में सक्रिय है। अपने वार्ड के मुद्दों सभा से सड़क तक उठाती रही है। निगम की राजनीति में मीनल चौबे के बाद सरिता दूबे का नाम रेस में आगे है।

वंदना राजपूत- संगठन राजनीति में सक्रिय रही है। पार्टी के पक्ष को मज़बूती के साथ रखा है। राजधानी की महिला मोर्चा में उनका चेहरा सबसे सक्रिय रहा है। उन्होंने महापौर पद के लिए दावेदारी भी की है। कहा है कि दावेदारी है, पार्टी के निर्णय लेगी वो मंजूर होगा। **प्रीति उपाध्याय**- संगठन में सक्रिय रही है, दावेदारी की है। प्रीति कुणाल शुक्ला। प्रबल दावेदारी है, खुशी है कि राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी ने ज़िम्मेदारिया दी है और सक्षम समझा है । शुरू से पार्टी के लिए काम करते आये है, पूरी उम्मीद है पार्टी टिकट हमें ही देगी। **दीप्ति दुबे**- पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी है और प्रमोद दुबे के साथ राजनीति में सक्रिय भी रही हैं। प्रमोद दुबे द्वारा उनकी पत्नी की दावेदारी बेहद अहम मानी जा रही है। **किरणमयी नायक**- किरणमयी नायक वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रायपुर नगर निगम की महापौर भी रही हैं। उनका नाम भी महापौर के चेहरे में मज़बूत नज़र आ रहा है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवाल

सरकारी कर्मचारी ने एक के बाद एक 2 बार निकाला टोकन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से जिला पंचायत की आरक्षण प्रकिया में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यहां लाटरी सिस्टम से जिला पंचायत 5 और 6 के लिए टोकन निकलवाया गया। इस दौरान आरक्षण कार्य में लगे कर्मचारी ने खुलेआम नियम का उल्लंघन करते हुए एक टोकन की जगह दो टोकन निकाला, जिसका विरोध किया गया।

शिकायतकर्ता हरिनाथ खुंटे के मुताबिक, टोकन निकालने पहुंचे व्यक्ति की जगह जबरन सरकारी कर्मचारी ने टोकन निकाला। इससे जिला प्रशासन की निष्पक्ष आरक्षण की पोल खुल गई। आरक्षण के कार्य में दो कर्मचारी ब्रजभूषण पटेल और बलभद्र पटेल लगे हैं। सचिव ब्रजभूषण पटेल ने आरक्षण के लिए एक की जगह दो टोकन निकाला, जिसका विरोध किया गया। शिकायतकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी से जिला पंचायत क्षेत्र 5 और 6 का फिर से आरक्षण प्रक्रिया कराने की मांग की है।

महापौर के लिए कांग्रेस नेताओं की पत्नियों की दावेदारी का विरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम में महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावेदारों की होड़ लग गई है। कांग्रेस में महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं की पत्नियों ने दावेदारी की है, जिस पर महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर नगर निगम में महिला आरक्षण के बाद सक्रिय महिला कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है।

महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रगति वाजपेयी ने पत्र में लिखा है कि महापौर के लिए पार्टी के नेता अपनी पत्नियों के नाम आगे कर रहे हैं। ये पार्टी के हित के खिलाफ है। महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सालभर महिला कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करती है। प्रदेश की सभी महिला आरक्षित सीटों पर सक्रिय महिला कांग्रेस और पीसीसी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए।

बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 दिसंबर को पूरी हुई। महिला आरक्षित महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए टिकट की दावेदारी की है। इसमें पूर्व महापौर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा समेत कई नाम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में एमएसपी रेट पर बंपर धान खरीदी

■ **छत्तीसगढ़ में अब तक 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से लगातार धान खरीदी हो रही है। अब तक लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 20.53 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 23 हजार 790 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दिया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख क्विंटल के पार पहुंच गया है। उन्होंने लिखा धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा गया है। किसानों की मेहनत का पूरा मान-सम्मान हमारी सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाइन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते हैं।

49.15 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव = धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 79.15 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। इसके एवज में 49.15 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 7 जनवरी 2025 को 65 हजार 321 किसानों से 3.41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 75 हजार 905 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 73 हजार 725 टोकन जारी किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल हैं। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 4 फरवरी धान खरीदी की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 नवंबर से 4 फरवरी तक प्रदेश के 24 लाख 72 हजार 310 किसानों ने धान बेचा था। 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी करते हुए सरकार ने अपने लक्ष्य को पार कर 144.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। धान खरीदी का यह आंकड़ा पिछले साल खरीफ सीजन 2022-23 की तुलना में 26 फीसदी ज्यादा था।

रायपुर नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर

■ **लोगों की सुनी समस्या, अहम निर्देश अधिकारियों को दिए**

रायपुर। रायपुर नगर निगम की सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होने के बाद प्रशासक ने कार्यभार संभाल लिया है। आज सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन्म मृत्यु शाखा में जाकर नागरिकों से जानकारी ली और उनकी समस्या जानी। जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गौरव ने वृद्ध महिला को चेयर पर बिठाकर उनकी समस्या जानी और अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास शाखा में पहुंचे और नागरिकों को समय पर रिस्पॉन्स करने निर्देशित किया। नगर निगम के बाजार और नजूल विभाग का निरीक्षण किया। स्वंय ही आवेदन की स्थिति का स्वयं देख

प्रकिया की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर गौरव ने प्रधानमंत्री आवास शाखा में आए आवेदन को लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं।

समाजिक और निराश्रित पेंशन शाखा का भी आज कलेक्टर गौरव सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निगम अधिकारी-कर्मचारी से कलेक्टर ने पूछा कि 31हजार पेंशन धारियों को कितने को पेंशन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण पता कर जल्द निराकरण करें।

राहुल तय करेंगे, कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री?

संतोष पाठक

चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को बतौर सीईसी अपनी आखिरी प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही अपने ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोपों का भी एक-एक करके जवाब देने की कोशिश की। दिल्ली में इस बार मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 है जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 71 लाख 73 हजार 952 है। जाहिर तौर पर, देश के कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिला मतदाता, चुनावी जीत-हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली की चुनावी लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को होने जा रहे मतदान में मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव, उनके अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण राज्य- पंजाब में सरकार होने के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली का केजरीवाल के लिए अपना महत्व है। अगर केजरीवाल दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो आम आदमी पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी उनका दबदबा कमजोर होता चला जाएगा। घोटाले के आरोप में जेल तक की यात्रा करने वाले अरविंद केजरीवाल यह बखूबी जानते और समझते हैं कि दिल्ली की हार एक बार फिर से उन्हें राजनीतिक रूप से अछूत बना देगी। क्योंकि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही मजबूरी में कई राज्यों में आप के साथ गठबंधन किया था लेकिन सच्चाई तो यही है कि सोनिया गांधी इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल पर कतई भरोसा नहीं करती है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और गांधी परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 2020 में, दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को सिर्फ 4.26 प्रतिशत मत मिला था और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत हुई है और अब अगर कांग्रेस अपने उस छीने हुए वोट बैंक के छोटे से हिस्से को भी वापस लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर केजरीवाल सहित आप के सभी उम्मीदवारों के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 53.57 प्रतिशत मत के साथ आप को 62 सीटें मिली थी जबकि 38.51 प्रतिशत मत पाने के बाद भी भाजपा के खाते में सिर्फ 8 सीटें ही आ पाई थी। आप और भाजपा के बीच 15.06 प्रतिशत का अंतर था। अगर कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मत प्रतिशत में 8-10 प्रतिशत का भी इजाफा कर पाती है तो फिर दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है यानी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। दिल्ली के चुनावी समीकरण से यह बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है कि आप और भाजपा के मुकाबले में सबसे कमजोर नजर आ रही कांग्रेस के आलाकमान यानी गांधी परिवार ने अगर पूरी ताकत के साथ दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो फिर राहुल गांधी ही यह तय करेंगे कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी ? वास्तव में दिल्ली का यह चुनाव राहुल गांधी के लिए फैसला करने वाला चुनाव होगा कि वह वाकई अपनी पार्टी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एकता के नाम पर अपनी पार्टी को कुर्बान कर देते हैं।

नये चीनी वायरस से चिन्ता में डूबी दुनिया

ललित गर्ग

मानव इतिहास की सबसे बड़ी एवं भयावह महामारी कोरोना को झेल चुकी दुनिया पर एक और नये चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के संक्रमण की खबर ने दुनियाभर को चिंता में डूबो दिया है, बाजार से लेकर सामान्य जन-जीवन तक में डर, खौफ, अफरा-तफरी एवं असमंजस्य का माहौल व्याप्त है। कोविड-19 और अन्य श्वसन वायरस की तरह एचएमपीवी भी खांसने, छींकने और संक्रमित लोगों के निकट संपर्क से उत्पन्न बूंदों या एरोसोल के माध्यम से फैलता है। बुखार, सांस फूलना, नाक बंद होना, खांसी, गले में खराश और सिरदर्द इसके सामान्य लक्षण हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों को इस संक्रमण के कारण ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो सकता है। एचएमपीवी के खिलाफ कोई टीका या प्रभावी दवा नहीं है और इलाज ज्यादातर लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए होता है। चीन में सांस की बीमारियों के बढ़ते मामलों की खबरों के बाद, भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ से स्थिति पर लगातार अपडेट देने का अनुरोध किया है।

नये वर्ष में प्रवेश की शुभबेला में एकाएक इस महामारी की खबर से दुनिया भौचक्क एवं खौफ में आ गयी है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के पांच साल बाद, चीन मौजूदा समय में नए वायरस एचएमपीवी से जूझ रहा है। इस वायरस ने चीन में हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां हालात बेकाबू हो रहा हैं, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि, हर बार की तरह चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी-जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग ज्यादा प्रभावित हुए है। चीन के साथ ही दुनिया के अनेक हिस्सों से इस महामारी से

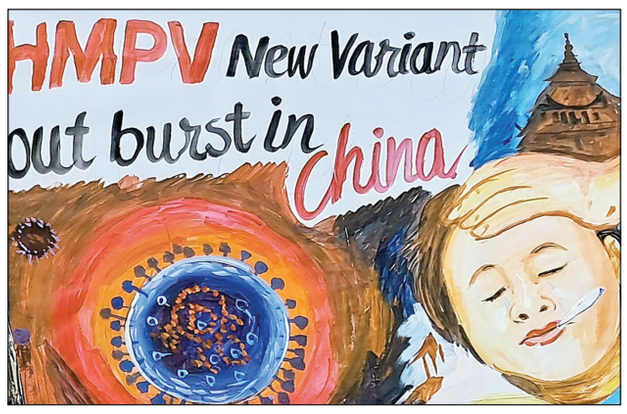

पीड़ित लोगों की खबरें आ रही है। भारत में भी चीन का खतरनाक वायरस एचएमपीवी पहुंच गया है। खबरों की मानें तो बेंगलुरु में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। बच्चे का ब्लड टेस्ट किये जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है। यह भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि, भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई।

चीन में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लूएंजा ए, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएमपीवी मामलों में वृद्धि के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है तथा 40 से 80 वर्ष की आयु के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। चीन की जिम्मेदार एजेंसियां इस वायरस के दुष्प्रभाव को घटाने में लगी हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि चीन इस रोग पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाएगा। चीन अपने यहां कोरोना वायरस पर भी लगाम लगाने में एक हद तक कामयाब रहा था। लेकिन वह दूसरे देशों में उसे फैलने से नहीं रोक पाया। लेकिन इस बार अब यह उम्मीद करनी चाहिए कि सजग चीन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने यहां से किसी भी संदिग्ध को किसी दूसरे देश की यात्रा न करने दें। साथ ही इस महामारी पर नियंत्रण पाने में जिस विधि एवं उपचार पद्धति से वह सफलता पाये, उसे समूची दुनिया से साझा करें, ताकि महामारी से महाविनाश का प्रकोप व्यापक न बन सके।

एचएमपीवी का संक्रमण व्यक्तिगत संपर्क से बढ़ रहा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी सामान को कोई स्वस्थ व्यक्ति छुए या उसके सम्पर्क में आये तो संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है। यह वायरस चूंकि नया है, तो इसका अभी कोई टीका नहीं है। इसकी कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है। यह अच्छी बात है कि अधिकांश मामलों में लोगों को मामूली समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग लक्षण के अनुरूप उपचार और आराम से ही ठीक होते जा रहे हैं। चीन ने साफ तौर पर कुछ बताया नहीं है, मगर अनुमान यही है कि गंभीर मामलों में लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने, ऑक्सीजन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मानें, तो इस वायरस का संक्रमण अक्तूबर महीने से ही बढ़ रहा है। अच्छा यही है कि यह बीमारी मौसमी साबित हो और कम से कम लोगों के जीवन पर असर डाले। कोरोना महामारी तो महाविनाश का कारण बनी थी, एचएमपीवी ऐसा अनर्थ ना करें।

चीन की साख कोरोना महामारी के कारण बहुत गिरी थी, दुनियाभर में लोगों के स्वास्थ्य पर हमला करने वाला चीन दुनिया की नजरों से गिर गया था। आखिर चीन अच्छी-अच्छी वस्तुओं, तकनीक एवं साजोसामान का निर्यात करते-करते महामारियों का निर्यातक क्यों बन गया? स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक क्रांति के लिये अग्रणी चीन अपने यहां आए दिन हो रहे ऐसे संक्रमण को लेकर सजग क्यों नहीं है? अब यह सवाल बिल्कुल जायज है कि वैज्ञानिक या कृत्रिम तरक्की की होड़ में कहीं चीन अपने लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य की अनदेखी तो नहीं कर रहा है? कहीं चीनियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त या बहुत कम तो नहीं हो गई है? वे बार-बार किसी-न-किसी प्रकार की महामारी की चपेट में आ रहे हैं और सम्पूर्ण मानव जाति को इससे पीड़ित बना रहे है तो यह गंभीर बात है। क्या इसका बड़ा कारण चीनी लोगों को खान-पान है? जरूरत से ज्यादा सुविधावादी जीवनशैली, कृत्रिम संसाधनों की प्रचुरता एवं अप्राकृतिक जीवन उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है।

ध्यान रहे कोरोना महामारी के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संतोषजनक नहीं थी। कोरोना महामारी की भयावहता के बावजूद वह चीन के प्रति उदार बना रहा। इसलिये एचएमपीवी महामारी के सन्दर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ गंभीरता दिखाते हुए पर्याप्त कदम उठायेगा? क्या उसने कोरोना महामारी के समय चीन से सही सवाल पूछे होते तो इस बीमारी के संभावित खतरे को नियंत्रित किया जा सकता था? क्या कोरोना बीमारी को लेकर विश्व को समय से सलाह न दे पाने में नाकाम रहने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? इस नयी महामारी को लेकर भी इन्हीं कारणों से डब्ल्यूएचओ पर ज्यादा विश्वास कैसे किया जा सकता है? भारत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ.अतुल गोयल ने शुक्रवार को कहा कि एचएमपीवी एक सामान्य सांस संबंधी वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। कुछ लोगों को, खासकर बुजुर्गों और शिशुओं को, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यह कुछ गंभीर या चिंताजनक नहीं है।' डॉ. गोयल ने भले से मनोवैज्ञानिक तरह से एचएमपीवी वायरस को गंभीर न बताकर इसके आतंक को कम कर दिया है, सरकार भी इस महामारी को लेकर सतर्क है, लेकिन फिर भी इस नये वायरस की त्रासदी एवं संकट से जूझ रहे विश्व-मानव को सावधान रहना चाहिए। विभिन्न देशों की सरकारों एवं डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना है। हर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो और महामारी का शिकार होने पर हर व्यक्ति को अच्छे प्रकार के इलाज की अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसे प्रयास करने है। इक्कीसवीं सदी की पहली रजत जयन्ती वर्ष की शुरुआत नये वायरस की महामारी के रूप में एक वैश्विक त्रासदी के साथ होना दु:खद है। ऐसी त्रासदी जो विश्व की बड़ी सत्ताओं को मानव कल्याण की नीतियों को अपनाने एवं इंसान को अपने जीवन मूल्यों और जीवनशैली पर पुनर्चिंतन करने को मजबूर कर रही है और उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त कर रही है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

हम कब कहते हैं कि उक्त पुराण के मुख्याँश के कर्ता पराशर जी नहीं है? परन्तु स्मरण रहे परशरोक्त भी यह पुराण अष्टादश पुराण संकलन के समय व्यास जी ने ज्यों का त्यों या उचित हेर फेर के साथ अपनी ग्रन्था- वलि में सम्मिलित नहीं किया- इसका आपके पास कुछ भी प्रमाण नहीं। शिवपुराण में मूल में ही महाशय जी के आक्षेप का समाधान कर दिया है, यथा:- पराशरकृत यत्तु पुराणं विष्णुबोधकम्। तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरभेदत:।। (शिव पु0 उत्तर0 मध्येश्वर माहा0)

अर्थात्- विष्णु भगवान् की महिमा का बोधक जो विष्णुपुराण पराशर जी ने बनाया था, वही व्यासकृत भाना जाता है, क्योंकि पुत्र और पिता का सर्वथा अभेद होता है [आत्मा वै पुत्रनामासि- इति श्रुते:] इसलिए पराशरोक्त विष्णुपुराण भी व्यास-संकलित ही है- इस में आक्षेप को अवकाश नहीं ।

(16) ग्रहम्मवैवर्तादि की भविष्य-वाणियों के पढ़ने से जाना जाता है कि ये पुराण मुसलमानों के भारताक्रमण के पश्चात् बने हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि काँची और काश्मीर-मण्डल का राज्य यवन भोगा करेंगे, यथा:- गान्धारे सिन्धुसौवीरे काञ्चीकाश्मीरमण्डलम्। भोक्ष्यन्ति निन्द्यकृतय: यवना: कलिदूषिता:।। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि जब मुसलमानी राज्य उक्त देशों में व्याप्त हो गया था, तब ब्रह्मवैवर्त पुराण बना था। यदि वस्तुत: भविष्यत्- वाणी होती तो यह लिखते कि सम्पूर्ण भारत यवनों के आधीन हो जाएगा, सो नहीं लिखा ।

(17) प्रतिवादी ने इस आक्षेप में समस्त भारत के बजाय देश- विशेषों में यवन राज्य कहना हेतु ठहराया है। यदि महाशय जी को भौगोलिक वर्णन-शैली का थोड़ा भी ज्ञान होता तो वह ऐसा आक्षेप करने का साहस न करते।

क्रमश: ...

प्रवासी भारतीय दिवस

अनन्या मिश्रा

हर साल भारत सरकार की तरफ से 09 जनवरी को %प्रवासी भारतीय दिवस% मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साल 1915 को इस दिन दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी की अपने देश भारत वापस लौटे थे। देश से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के उद्देश्य से भारत की राजधानी दिल्ली में 09 जनवरी से 11 जनवरी 2003 के बीच पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन संपन्न किया गया था। आपको बता दें कि लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी को प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का श्रेय जाता है।

आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। साल 2003 से इस

दिन को मनाए जाने की शुरूआत की गई। इस मौके पर दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतीयों को सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा जाता है। इस दिन को मनाए जाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों को देश के प्रति भावना, सोच की अभिव्यक्ति और देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए के मंच उपलब्ध कराना है। विश्व के सभी देशों में युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ने और अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क से जोड़ना है।

इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय श्रमजीवियों की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को सुनना और उनको दूर करने की कोशिश करना है। इसके साथ ही देश के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करने और निवेश के अवसर को बढ़ावा देना है।

आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मान देश के प्रवासी भारतीय के मामलों का मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कार है। हर साल इस दिन राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के समापन सत्र में प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। इन पुरस्कार विजेताओं में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अद्वितीय योगदान से प्रवासी भारतीय समुदाय का नाम रोशन किया है। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए 27 विभूतियों का चयन हुआ है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान के लिए चुनी गई ये हस्तियां 23 देशों में रहती हैं। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवसाय समेत कई अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान है।

इसमें से कुछ प्रमुख नामों में ब्रिटेन से बैरोनेस उषा कुमारी पराशर (राजनीति में), अमेरिका में डॉ. शर्मिला फोर्ड (समुदाय सेवा में) शामिल हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाओं को भी यह सम्मान दिया जाएगा।

जस्टिन ट्रूडो से कहां हो गई चूक, कनाडा में कब होंगे चुनाव

अभिनय आकाश

लोग अक्सर मुझे कमतर समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हल्का हूं। अगर मैं लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से लेने लगेंगे। साल 2012 का वो दौर जब कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद पैट्रिक ब्राजेउ ने ट्रूडो को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी नेतागिरी की कुछ छाप छोड़ना चाहते हैं तो मुझे बॉक्सिंग रिंग में हरा कर दिखा। पैट्रिक कराटे के ब्लैक बेल्ट थे। ट्रूडो बॉक्सिंग किया करते थे लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे। मार्च 2012 में बॉक्सिंग मुकाबले में तीसरे राउंड में ही जस्टिन ने पैट्रिक को हरा दिया। जिसके बाद लिबरल पार्टी की कमान संभालने को लेकर वोटिंग हुई और 80 फीसदी के साथ 2013 में जस्टिन ने जीत दर्ज की। कट टू साल 2024 की शुरुआत 6 जनवरी का दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आए और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

ट्रूडो ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि वे आंतरिक लड़ाइयों के कारण अगले चुनावों के दौरान वह नेता नहीं रह सकते। उन्होंने लिबरल पार्टी का नया नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की योजना बनाई है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ट्रूडो ने कहा कि मैं किसी लड़ाई में आसानी से पीछे नहीं हटता, खासकर जब यह हमारी पार्टी और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन मैं यह काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कनाडा के लोगों के हित और लोकतंत्र की भलाई मेरे लिए सर्वोपरि है। ट्रूडो खुद ये मान रहे हैं कि अगर मेरे चेहरे के साथ लिबरल पार्टी चुनाव में जाती है तो कंजर्वेटिव के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ सकती है।

कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाने

के बाद कनाडा के साथ भारत के संबंधों में गिरावट आई। सितंबर 2023 में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। यह तब हुआ जब कनाडा ने घोषणा की कि वह निज्जर की हत्या से भारतीय सरकारी एजेंटों को जोड़ने वाले आरोपों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उस समय कहा था कि कनाडाई राजनयिक का निष्कासन हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर बढ़ती चिंता पर था। भारत ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कनाडा में अपने वीज़ा संचालन को भी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था। अक्टूबर 2023 में, कनाडा ने भारत से अपने 40 राजनयिकों को वापस बुला लिया क्योंकि नई दिल्ली ने राजनयिक उपस्थिति में समानता का आह्वान किया था। पिछले अक्टूबर में संबंधों में और खटास आ गई जब नई दिल्ली ने छह उच्च रैंकिंग वाले कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। ओटावा ने कहा कि उसने जून 2023 में निज्जर की हत्या में उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य अधिकारियों को रुचि के व्यक्तियों के रूप में नामित करने के बाद छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। तब विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि यह नवीनतम कदम उन बातचीत के बाद उठाया गया है जिसमें बिना किसी तथ्य के फिर से दावे किए गए हैं। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एक सोची-समझी रणनीति है। भारत का कहना है कि कनाडा ने अपने अधिकारियों को निज्जर की हत्या से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं दिया है।

भारत ने ट्रूडो सरकार पर कनाडा को खालिस्तानी चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली ने कनाडाई सरकार पर वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। 2016 में, ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मंत्रिमंडल में भारत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में अधिक सिख हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा 771,790 सिखों का घर है, जो भारत में पंजाब के बाहर दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी है। कनाडा की राजनीति में सिखों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत के साथ संबंधों में गिरावट के अलावा ट्रूडो को अपनी पार्टी के भीतर आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 21 लिबरल सांसदों ने सार्वजनिक रूप से ट्रूडो से पद छोड़ने का आग्रह किया है, उनमें से कई 16 दिसंबर, 2024 को फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद थे। पिछले अक्टूबर में, 24 लिबरल सांसदों ने पार्टी के दो संघीय उपचुनाव हारने के मद्देनजर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

कोविड-19 महामारी के बाद से कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनकी सरकार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को कम करने में विफल रही है, जबकि जीवन-यापन संकट ने कई लोगों के लिए आवास को अप्राप्य बना दिया है। लिबरल पार्टी के संघीय चुनाव हारने की भविष्यवाणी की गई है। कंजर्वेटिव पार्टी फिलहाल उदारवादियों से 21 अंक आगे है। पिछले साल इप्सोस के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि केवल 28 प्रतिशत कनाडाई चाहते हैं कि ट्रूडो फिर से निर्वाचित हों और केवल 26 प्रतिशत उदारवादियों को वोट देंगे। ट्रूडो द्वारा भारत को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाने को कनाडा के चुनावों में कथित चीनी हस्तक्षेप से ध्यान भटकाने के तौर पर भी देखा जा रहा है।

विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि चीन 2019 और 2021 से कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसे लेकर बड़े विवाद हैं। चाइनागेट से ध्यान हटाने और ध्यान भटकाने के लिए, जिसमें ट्रूडो को एक कमजोर नेता के रूप में लेबल किया जा रहा है। ट्रूडो ने बहुत ही समझदारी से अपने देश के भीतर अपने नेतृत्व की विफलताओं पर ध्यान भटकाने के लिए भारत को बढ़ावा देने के बारे में सोचा। इसलिए हम इससे अधिक की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ट्रूडो ने चाइनागेट के संबंध में अपनी समस्याओं और परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए भारत को लक्षित करने का एक सचेत निर्णय लिया।

जिस वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे ठीक उसी दरमियान कनाडा में भी चुनाव भी हो रहे हैं। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव हैं। कनाडा में दो पार्टियां मुख्य तौर पर हैं। एक कंजर्वेटिव और दूसरी लिबरल पार्टी है। लिबरल पार्टी से दो चुनाव जीतकर ट्रूडो सत्ता में आ चुके हैं। उनके पिता पियरे ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 16 दिसंबर 2024 को कनाडा की फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। उस दौरान लोगों ने कहा कि ट्रूडो ने उन्हें डिमोट किया।

आज का इतिहास

1854 जर्मन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पिट्सबर्ग, यू.एस.ए. में टेउटोनिया बाज़ारिया की स्थापना की गई।
1855 क्लैपर गाइडिंग स्टार अटलांटिक सागर में गायब गया जिसमें 480 लोग मरे गए।
1857 कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फाल्ट के एक हिस्से में 7.9 मेगावॉट का भूकंप आया और इसे लास वेगास जितना दूर पूर्व में महसूस किया गया था।
1873 19वीं शताब्दी के सबसे साहसी यूरोपीय शासकों में गिने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय का निधन हुआ।
1878 अम्बर्टो आई इटली का राजा बनाया गया।
1909 निम्रोड अभियान का नेतृत्व करने वाले अर्नेस्ट शेकलटन ने दक्षिणी ध्रुव से ब्रिटिश ध्वज 97 नॉटिकल मील (180 किमी) लगाया, जो उस समय अब तक का सबसे दूर पहुंच गया है।
1923 मेमेल टेरिटरी के लिथुआनियाई निवासियों ने फ्रांसीसी नियंत्रण के तहत एक अनिवार्य क्षेत्र के रूप में क्षेत्र को छोड़ने के लिए लीग ऑफ नेशंस के फैसले के खिलाफ विद्रोह किया।
1936 एक भूकंप,कोलंबिया में 250 लोग मारे गए।
1941 यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में छह हजार यहूदियों की हत्या हुई।
1945 बेस्टांग दर्रा की लड़ाई मनीला के उत्तर में शुरू हुई।
1951 अमेरिका के न्यूयॉर्क में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय खुला।
1960 मिस्र में नील नदी पर आसवान नामक बांध का निर्माण आरंभ हुआ।
1962 क्यूबा और सोवियत संघ ने एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किया।
1972 आरएमएस क्वीन एलिजाबेथ, एक महासागर लाइनर जो केंटर्ड व्हाइट स्टार लाइन के लिए अटलांटिक महासागर को बहाती है, हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में आग से नष्ट हो गई थी।
1972 नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लॉस एंजिल्स लेकर्स मिल्वौकी बक्स से हार गए, जो 33-गेम जीतने वाली लकीर को समाप्त कर रही थी, जो अमेरिकी पेशेवर खेलों में किसी भी टीम की सबसे लंबी थी। 1974 हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, गायक और अभिनेता फरहान अख्तर का जन्म हुआ।
1981 अमेरिकी प्रतिनिधि रेमंड एफ. लेडरर को एब्सकैम कांड में उनकी भूमिका के लिए रिश्वत और साजिश का दोषी ठहराया गया था, लेकिन तीन और महीनों तक उनके कार्यकाल की सेवा जारी रही।

दिल्ली चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे हावी, किन चेहरों के दम पर जीतने की तैयारी?

कीर्तिवर्धन मिश्र

दिल्ली विधानसभा चुनाव का एलान बीते मंगलवार को गया। इस बार यह मुकाबला तीन बड़े दलों- सत्तासीन आम आदमी पार्टी, विपक्षी भाजपा और पिछले चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच हो रहा है। तीनों ही दल अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीटें लाने का दावा कर रहे हैं।

दिल्ली में बीते 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2013, 2015 और फिर 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होने की एक बड़ी वजह है आप पर लगे आरोप। दरअसल, पहले तीन चुनावों में आप ने दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभाला। हालांकि, इस बार पहले शराब घोटाला उसके बाद मुख्यमंत्री बंगले के रेनोवेशन से जुड़े आरोप सामने आने के चलते केजरीवाल एंड कंपनी की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में कद्दावर नेताओं का नाम देकर यह साबित कर दिया है कि वह इस चुनाव में किसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहतीं।

इस बीच यह जानना अहम है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दों का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा वे कौन से चेहरे होंगे, जिनके दम पर राजनीतिक दल दिल्ली के चुनाव को जीतने की तैयारी रहे हैं।

क्या होंगे इस चुनाव में मुद्दे?

1. मनी लॉन्ड्रिंग-शराब घोटाला केस

दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उसके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जिसके चलते बीते तीन से चार वर्षों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेताओं को जेल तक जाना पड़ा है। इनमें सबसे बड़े आरोप रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला केस से जुड़े आरोप, जिन्हें लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आप पर हमलावर रहे हैं।

2. यमुना की सफाई

दिल्ली विधानसभा चुनावों में दूसरा बड़ा मुद्दा यमुना नदी की सफाई से जुड़ा है। दरअसल, आप सरकार ने ही वादा किया था कि उसके सरकार में आने के बाद यमुना नदी को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे। हालांकि, 12 वर्ष बाद भी इस पवित्र नदी में प्रदूषण पहले से बदतर स्थिति में है। बताया जाता है कि आप ने इसे लेकर बड़ी धनराशि भी खर्च की है। लेकिन उसकी इन कोशिशों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इसके उलट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली हाईकोर्ट तक ने आप सरकार की खिंचाई की है और उससे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

इस पर विपक्ष ने आप को घेरते हुए कहा कि दिल्ली

सरकार को यमुना की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह पैसा अपने झूठे प्रचार पर खर्च किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट शासन के कारण दिल्ली से पैदा होने वाले गन्दे जल को एसटीपी में साफ नहीं किया जा रहा है और इसकी कीमत यमुना और दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ रही है।

3. शीशमहल मुद्दा

दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले जो एक और मुद्दा आप के लिए सिरदर्द बनकर उभरा है, वह है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में रहने के दौरान इसके रेनोवेशन कराने का मुद्दा। हाल ही में सीएजी ऑडिटर रिपोर्ट के हवाले से एक अखबार ने दावा किया है कि शुरू में सीएम के आवास के रेनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ रुपये बताई गई थी। लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.62 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33.66 करोड़ रुपये थी। पिछले एक साल से इस मुद्दे को उठा रही भाजपा को इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद आप पर वार करने का और मौका मिल गया। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बंगले पर 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

विपक्ष का कहना है कि 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी। उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसके निर्माण में अनियमितताएं बरती गईं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2024 में जो इन्वेंटरी घोषित की है और जो समान दिखाया है कि यह पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वह समान कहां से आया। वह किसका पैसा है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा।

4. वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप

दिल्ली में एक और मुद्दा, जिस पर बीते कई महीनों से राजनीति हो रही है, वह है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है और भाजपा पर नई दिल्ली सीट में बड़ा खेल करने का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मर्लेना ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। आप का आरोप है कि नई दिल्ली में 10 फीसदी वोटर्स को जोड़ा गया है, जबकि पांच फीसदी वोट काटे गए हैं। यह एक षड्यंत्र चल रहा है।

इससे पहले केजरीवाल ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा था और कहा था कि वह दिल्ली विधानसभा में वोट कटवाने के साथ फर्जी नाम जुड़वाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बाहर से लोगों को लाकर उनके फर्जी वोट बनवा रही है और आप समर्थकों का वोट कटवाने, फर्जी वोट बनवाने के साथ वोट के लिए पैसे दे रही है। आप के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया है और वोटर लिस्ट के सत्यापन तक की बात कही है। हालांकि, आप ने चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया है।

5. महिलाओं के लिए सम्मान राशि

देश में पिछले विधानसभा चुनाव- झारखंड और महाराष्ट्र में हुए थे। इन दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों के चुनाव जीतने की एक बड़ी वजह महिलाओं पर केंद्रित आर्थिक मदद की योजनाओं को माना गया था। आम आदमी पार्टी ने इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए हाल ही में एलान किया था कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लागू कर रही है और इसके तहत वह 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की वित्तीय सहायता डालेगी। केजरीवाल ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा।

हालांकि, आप इस योजना को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है। दरअसल, इस एलान के बाद दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में ऐसी गैर-मौजूद योजनाओं पर विश्वास न करें। आप ने दिल्ली के विभाग के इस नोटिस को भाजपा की साजिश करार दिया था।

उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इस योजना को लेकर आप को निशाने पर लिया है। वीके सक्सेना ने आप की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दिए हैं। एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया था कि गैर-सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी जांच कराएं और कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

आप की इस योजना के जवाब में कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने के लिए चुनाव जीतने के बाद प्यारी दीदी योजना लाने का एलान किया है। इसके तहत कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं की आर्थिक मदद का मुद्दा लगातार गर्म रहने वाला है।

चुनाव प्रचार के चेहरे

1. अरविंद केजरीवाल

इस बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल फिर मैदान में हैं। वे 2013 से ही आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए पार्टी को जीत दिला रहे हैं। 2013 में दिल्ली विधानसभा के लिए जब चुनाव कराए गए। तब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती देने की ठानी। वे इस चुनौती में सफल भी रहे और उन्होंने शीला दीक्षित और कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म कर सरकार बनाने में सफलता हासिल की। 2013 के बाद 2015 और 2020 में भी अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीता और लगातार राजधानी के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए।

2. संदीप दीक्षित

नई दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद एवं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। पार्टी को भरोसा है कि संदीप यहां से अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 2004 और 2009 में पार्टी के टिकट पर जीतकर लोकसभा सांसद रहे हैं। हालांकि, 2014 में मोदी लहर के दौरान उन्हें अपनी यह सीट गंवानी पड़ी। बाद में पार्टी ने उन्हें संगठन में ही पद सौंपे। हालांकि, शीला दीक्षित के दिल्ली सीएम पद से हटने के बाद कांग्रेस में संदीप दीक्षित धीरे-धीरे हाशिए पर चले गए।

3. प्रवेश वर्मा

भाजपा ने अपनी पहली सूची में ही प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का एलान कर दिया। उनके नाम की घोषणा भाजपा के लिए कितना बड़ा कदम थी, यह इसी बात से पता चलता है कि यहां से उनके लड़ने की चर्चा पिछले महीने से ही चल रही थी। इस सीट से पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव और आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए विनोद बिन्नी दावेदारी ठोक रहे थे। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव ही लड़ा था। तब वे महरौली सीट से खड़े हुए और उन्होंने योगानंद शास्त्री को हराया था, जो कि दिल्ली विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके थे।

4. आतिशी मर्लेना

इस बार के विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट पर हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी विधायक हैं। यहां आतिशी की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पहले ही एलान कर दिया था कि उनकी (नई दिल्ली सीट) और आतिशी की कालका सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी चुनाव जीती थीं, उन्हें करीब 55,897 वोट मिले थे। आतिशी को सितंबर में ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था। इसी के साथ वे दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन गई थीं। आम आदमी पार्टी अपने आठ साल के कार्यकाल में जिन उपलब्धियों को सबसे ज्यादा बार गिनाती रही है उनमें शिक्षा का क्षेत्र सबसे ऊपर है और इसका बहुत बड़ा श्रेय आतिशी को जाता है।

5. अलका लांबा

मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अल्का लांबा को कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अल्का वर्ष 2013 में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गईं थीं और वर्ष 2015 में चांदनी चौक से विधायक चुनी गईं थीं, लेकिन वर्ष 2019 में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछली बार वे कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थीं, लेकिन हार गईं थीं।

6. रमेश बिधूड़ी

भाजपा ने कालकाजी सीट से ही आतिशी को चुनौती देने के लिए रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। हाल ही में वे आतिशी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी कर के घिर चुके हैं। हालांकि, दिल्ली की राजनीति में वे काफी पुराना नाम हैं। उन्होंने 2003 से 2008 तक भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके बाद 2008 में वह दिल्ली के भाजपा दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाए गए। वह 2003 से मई 2014 तक दिल्ली के विधायक भी रहे। 2014-2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधूड़ी शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति और पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समित के सदस्य भी रहे हैं।

7. मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार अपनी पटपड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा सीट आप का गढ़ मानी जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर 2013 में आप ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। यहां आप के प्रवीण कुमार मौजूदा समय में विधायक हैं। हालांकि, इस बार इस सीट से मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है।

राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों में टकराव, समाधान क्या

पूनम आई. कौशिश

जब से पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब से उनके मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार के साथ संबंध सुचारू नहीं हैं और कल तब अभूतपूर्व टकराव देखने को मिला, जब राज्यपाल अपना पारंपरिक अभिभाषण दिए बिना राज्य विधानसभा सत्र से चले गए। इसका कारण क्या है?

राष्ट्रगान का खुल्लमखुल्ला अपमान। राज्य गान के बाद राष्ट्रगान नहीं गाया गया। स्टालिन ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बचकानी हरकत है। वह निरंतर लोगों का अपमान करते रहते हैं। जब उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करना है तो फिर वह राज्यपाल के पद से क्यों चिपके हुए हैं। इससे पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा से यकायक चले गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें अभिभाषण के पाठ से अलग भाषण दिया था।

रवि द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यकरण के बारे में ब्यौरा मांगकर शासन के मामलों में दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के मुद्दे पर मंत्री पहले से नाराज हैं और वह राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वे राज्य में समानांतर सरकार चला रहे हैं। नवंबर में द्रमुक ने एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की और शिकायत की कि वे राज्य सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध करते हैं और 20 विधेयकों को स्वीकृति देने में अनुचित विलंब कर रहे हैं। आग में घी का कार्य रवि द्वारा स्टालिन के बेटे द्वारा सनातन धर्म को समाप्त करने के बारे में दी गई विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उनकी आलोचना ने किया। हाल ही में रवि ने गिरफ्तार मंत्री

सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का निर्णय किया, किंतु बाद में उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। शायद इसका कारण द्रमुक द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिह्न उठाना और संघवाद की वकालत करने से है। पार्टी के संस्थापक अन्नादुरई ने राज्यपाल की भूमिका की तुलना एक बकरे की दाढ़ी से की थी और कहा था कि दोनों अनावश्यक हैं। अनेक बार उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों को स्वीकृति न देने, राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति करने, विपक्ष शासित राज्यों में शिक्षा और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करने आदि को लेकर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और राज्य सरकारें न्यायिक हस्तक्षेप के लिए उच्चतम न्यायालय जाने के लिए बाध्य हुईं। इससे एक मूल प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल स्वयं में कानून बन गए हैं? क्या विपक्ष शासित राज्यों में विधायिकाएं उनकी दया पर निर्भर हैं? क्या इससे देश का संघीय ढांचा कमजोर नहीं होगा? राज्यपाल द्वारा नियमों और कानूनों की गलत व्याख्या और अपने निष्कर्ष निकालने के अनेक उदाहरण हैं, ताकि वे और केन्द्र में उनके आका खुश हो सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के साथ टकराव के अनेक उदाहरण हैं, जैसे दिल्ली में सक्सेना, केजरीवाल और आतिशी, महाराष्ट्र में पूर्व राज्यपाल कोश्यारी और ठाकरे, पश्चिम बंगाल में बोस-ममता, तेलंगाना में सौंदर्यराजन और चन्द्रशेखर राव, केरल में खान-पिनाराई आदि। केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह राज्यपाल के पद का उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग करती है और उन्होंने राज्यपाल के पद को केन्द्र की कठपुतली बनाया है, जो केन्द्र के इशारों पर हमेशा राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए तैयार रहता है। विसंगति देखिए।

एक राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में लौट आता है और इस तरह उस परिपाटी और परंपरा को बदल देता है। कांग्रेस के शिंदे ने नवंबर 2004 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया और उन्हें उसी दिन आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दो वर्ष बाद वह पुनः राजनीति में आए और उन्हें कांग्रेस ने यू.पी.ए. सरकार में केन्द्रीय विद्युत मंत्री तथा उसके बाद 2012 में केन्द्रीय गृह मंत्री बनाया। यही स्थिति मिजोरम में भाजपा के राज्यपाल राजशेखरन की है, जिन्होंने 2019 में राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया और केरल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस वातावरण में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति इस आधार पर नहीं की जाती कि वह व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, अपितु राज्यपाल के पद पर नियुक्ति सेवानिवृत्त हो रहे नौकरशाहों के लिए राजनीतिक लॉलीपाप के रूप में विदाई उपहार तथा असुविधाजनक प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक सुविधाजनक पद के रूप में की जाती है और वर्तमान में ऐसे राज्यपालों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। उसकी नियुक्ति का मूल मानदंड यह है कि क्या वह एक चमचा बन सकता है और इसीलिए विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल केन्द्र का एक सुविधाजनक औजार बन गया है जहां पर वह परोक्षी के माध्यम से सरकार चलाता है। इसके अलावा राज्यपाल का उपयोग अक्सर केन्द्र द्वारा राज्य में किसी भी कीमत पर अपनी सरकार स्थापित करने के लिए एक सुविधादाता के रूप में भी किया जाने लगा है और जिससे यह पद बदनाम हुआ है। यह सब कुछ एक स्वस्थ लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। समय आ गया है कि राज्यपाल उस कार्य को करें, जिसके लिए वे नियुक्त किए गए हैं अर्थात वे एक निगरानीकर्त्ता के रूप में हैं और उन्हें निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। यदि वे अपने संवैधानिक दायित्वों को त्याग दें और अपनी अंतरात्मा को केन्द्र में अपने आकाओं के पास गिरवी रख दें तो इस पद की जरूरत नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक नई विधि ढूंढी जानी चाहिए, जिसमें राज्य सरकारों से परामर्श पर्याप्त नहीं है क्योंकि कुछ राज्य सरकारें केन्द्र का समर्थन कर सकती हैं, इसकी बजाय राज्यसभा को नियुक्ति से पहले राज्यपाल पद के उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और उसकी उपयुक्तता की जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रपति को भी राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिएं, जिससे उन्हें किसी व्यक्ति के बारे में उसकी राजनीतिक संबद्धता और राजनीति के संबंध में गुमराह नहीं किया जा सके और केवल वे, जो राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ हों।

दिल्ली की सबसे चर्चित सीटों में कालकाजी

संध्या

दिल्ली में विधानसभा की तारिखों का एलान हो चुका है। राजधानी में 5 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस चुनाव में कालकाजी सीट सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। मुख्यमंत्री आतिशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को उतारा है। कालकाजी सीट पर पहला विधानसभा चुनाव साल 1972 में हुआ था। इस चुनाव में नतीजा कांग्रेस के टिकट पर उतरे वी.पी. सिंह के पक्ष में रहा। साल 1998 में कालकाजी सीट पर दो पुराने चेहरों के बीच मुकाबला हुआ। जहां भाजपा से मौजूदा विधायक पूर्णिमा सेठी उतरीं तो वहीं कांग्रेस ने सुभाष चोपड़ा पर फिर दांव खेला। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा ने भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा सेठी को 5244 वोट से शिकस्त दी। सुभाष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2003 में कालकाजी में मुकाबला दो पुराने चेहरों के बीच हुआ। मौजूदा विधायक सुभाष चोपड़ा कांग्रेस का चेहरा थे तो भाजपा ने पूर्व विधायक पूर्णिमा सेठी को टिकट दिया। चुनावी बाजी फिर कांग्रेस ने मारी और सुभाष 17644 मत से विजयी हुए। 2008 विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट नए रूप में अस्तित्व में आई। नए रूप में आए सीट पर चुनावी नतीजा कुछ नहीं बदला और तीसरी बार सुभाष चोपड़ा विजयी हुए। कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के जय गोपाल अबरोल को 13389 वोट से परास्त किया। दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। कालकाजी विधानसभा सीट पर मुकाबला पिछले चुनावों से अलग रहा। चुनाव नतीजे आए तो भाजपा को जीत मिली लेकिन उसे टक्कर नई-नवेली आम आदमी पार्टी से मिली। भाजपा उम्मीदवार हरमीत सिंह ने आप के धर्मबीर सिंह को 2044 वोट से हराकर यह चुनावी बाजी अपने नाम की। भाजपा को 30683 और आप को 28639 वोट मिले थे। 2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में कालकाजी सीट पर भाजपा और आप के बीच मुकाबला हुआ। 19769 वोट से चुनाव जीतकर आप ने यहां अपना खाता खोला। आप उम्मीदवार अवतार सिंह कालकाजी को 55104 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी हरमीत सिंह कालका 35335 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। कालकाजी के नतीजों की बात करें तो यहां से आप की तरफ से प्रमुख नेता आतिशी को जीत मिली। आप नेता ने भाजपा के धर्मबीर सिंह को 11393 वोट से पटखनी दी थी। आप को 55897 वोट जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा को 44504 वोट मिले। इस बार आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा को उतारा है। चेहरों के कारण कालकाजी सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। वहीं भाजपा ने यहां से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। कालका सीट से उम्मीदवार बनाए गए बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से विवादों में हैं।

मिल्कीपुर सीट पर योगी और अखिलेश की सियासी टक्कर, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल

अजय कुमार

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह उपचुनाव 5 फरवरी 2025 को आयोजित होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी 2025 को होगी। इस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने %मिशन मिल्कीपुर% के तहत पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यह सीट उनके लिए विशेष महत्व रखती है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद, योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सपा के खिलाफ अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है।

मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग की तारीख के ऐलान के साथ ही, यूपी सरकार ने इस उपचुनाव के लिए अपनी

पूरी मंत्रिमंडल टीम को सक्रिय कर दिया है। सात प्रमुख मंत्रियों को मिल्कीपुर के विभिन्न वर्गों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीशचंद्र यादव, स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश चंद्र शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और जेपीएस राठौर शामिल हैं। ये सभी मंत्री बूथ स्तर पर बैठकें कर वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। वह किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करे।

मिल्कीपुर की यह सीट योगी के लिए न केवल एक चुनावी चुनौती है, बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। इस सीट को लेकर उनकी चिंता इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों के बावजूद मिल्कीपुर का पांचवीं बार दौरा किया है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को बूथ मजबूत करने और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने का संदेश दिया। योगी की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि वह इस उपचुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं और उनकी सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है।

समाजवादी पार्टी के लिए भी यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, और इस सीट पर भाजपा के खिलाफ सपा ने अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित किया है। सपा के लिए यह चुनौती इसलिए और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि, नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में सपा को निराशा हाथ लगी थी, जहां पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है।

मिल्कीपुर सीट छह महीने से रिक्त पड़ी है, क्योंकि सपा के विधायक अवधेश प्रसाद ने 13 जून, 2024 को इस्तीफा दे दिया था। 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे को छह महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, लेकिन मिल्कीपुर सीट का मामला अदालत में विचाराधीन था, जिसके कारण इस सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं घोषित हो पाई थी।

मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में इस सीट से सपा के विधायक अवधेश प्रसाद के चुनाव को उनके नामांकन पत्रों में विसंगतियों का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। हालांकि, चुनाव याचिका को वापस लेने के बाद यह मामला अब तक लंबित था। अब चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की तारीख तय कर दी है, और राजनीतिक दलों के लिए यह लड़ाई और भी रोमांचक होने वाली है।

बेहतर करियर चाहिए तो इन बातों का रखें ध्यान, कामयाबी कदम चूमेगी!

एक अच्छा करियर ऑप्शन बेहतर भविष्य की सीढ़ी की तरह होता है. अच्छे परफॉर्मेंस की रेस और बोर्ड परीक्षा में स्कोर करने के लिए एक छात्र को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका फल तभी मिलेगा जब वह सही करियर का रास्ता चुने, लेकिन इसे कैसे किया जाए, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है. आइए आज हम आपको ऐसे जरूरी टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो 12वीं क्लास पास करने के बाद एक बेहतर करियर विकल्प चुनने में आपकी मदद कर सकते हैं.

सोचकर रिसर्च करें

12वीं क्लास के बाद अपना करियर चुनने से पहले अपनी रूचि पर ध्यान दें. अब जब आपकी बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो उस विशेष विषय के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो. आप साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसे आप खुद से पढ़ते हों, उस एक विषय को ढूंढते हैं और जानकारी जुटाते हों. सबसे पहले उस विषय के बारे में सोचें और तब भविष्य में उस ऑप्शन के स्कोप पर विचार करें और रिसर्च करें.

सलाह भी जरूरी है

अगर आप किसी खास विषय में करियर बनाने का मन बना रहे हैं. उस विषय में आगे बढ़ने से पहले अपने माता-पिता, दोस्तों, आस-पड़ोस के शिक्षित लोगों और अपने टीचर से बात करें. उनकी सलाह ले सकते हैं. जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें और तब करियर का चुनाव करें.

कोर्स से जॉब तक के लिए मार्केट रिसर्च करें

करियर का चुनाव करने से पहले मार्केट रिसर्च अच्छा ऑप्शन है. आप जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें जैसे उसकी पढ़ाई कहां-कहां से हो सकती है, कहां कितनी फीस ली जा रही है, उस कोर्स के बाद क्या और कहां जॉब ऑप्शन्स हैं, फ्यूचर में इसका कितना स्कोप है आदि.

भेड़ चाल से बचें

अकसर छात्र दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य से इन्फ्लुएंस होकर भेड़ चाल यानी दोस्तों के पीछे-पीछे बेहतर करियर की तलाश में निकल पढ़ते हैं. कई बार ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है लेकिन इससे अच्छा है कि आप खुद पर विश्ववास रखें और अपनी योग्यता, क्षमता, रूचि और ज्ञान के आधार पर सही करियर का चुनाव करें.

पसंद-नापसंद की लिस्ट बनाएं

उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पसंद और नापसंद करते हैं. उदाहरण- आपको कौन से विषय सबसे ज्यादा पसंद हैं, क्या आप आर्ट्स में रुचि रखते हैं, क्या आप साहसी हैं, क्या आप कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग आदि में रुचि रखते हैं. अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर अपने लिए सही करियर चुनें.

शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं

अगर आप किसी विषय में परफेक्ट हैं और उसी से संबंधित फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी अच्छा ऑप्शन है. इन दिनों कई टॉप कॉलेज छात्रों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन देते हैं. आपको सिर्फ थोड़ा सर्च करने की जरूरत है.

नौकरी चाहिए तो ऐसे बनाएं सोशल मीडिया प्रोफाइल

आजकल नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपका ज्ञान और स्किल्स ही काफी नहीं है, सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। आपने अपने फेसबुक पर क्या लिखा या ट्विटर पर कैसे ट्वीट किए या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपके बारे में क्या कहती है। आप सोशल मीडिया पर कैसे लोगों के संपर्क में हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब कंपनियां ये सब भी नौकरी देने से पहले देख रही हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नजरिये के बारे में पता लगाना बहुत आसान हो गया है। यही वजह है कि मल्टीनेशनल और स्टार्टअप कंपनियां नौकरी पर रखने से पहले आवेदक के प्रोफाइल को परखती हैं। इससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि आवेदक उनकी कंपनी में फिट बैठता है या नहीं।

सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि होना जरूरी

इन सोशल मीडिया प्रोफाइल से कंपनियों को आवेदकों की रूचि, उसकी प्राथमिकताएं और विश्वसनीयता के बारे में पता चलता है, जिस आधार पर उनके लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करना आसान होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर नौकरी मिले, तो ज्ञान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर आपकी सकारात्मक छवि भी होनी चाहिए। करीब 30 फीसदी कंपनियां आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह देखती हैं कि अन्य लोग आवेदकों के बारे में क्या राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक सर्वे में शामिल 60 फीसदी नियोक्ताओं ने उम्मीदवारों की ऑनलाइन मौजूदगी को परखने के बाद उन्हें खारिज कर दिया। इसका बड़ा कारण था उम्मीदवार के ऑनलाइन प्रोफाइल और रेज्यूमे में दी गई शैक्षिक योग्यता में अंतर। आवेदन के खारिज होने का बड़ा कारण था, पिछली कंपनी या अपने स्कूल-कॉलेज को बुरा बताने वाले पोस्ट डालना। इसके अलावा यह ध्यान रखें कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में कहीं भी बुरा न कह रहे हों।

सोच-समझकर सोशल मीडिया पर करें पोस्ट

वैसे तो सोशल मीडिया साइटों पर आम तौर पर लोग अपनी फोटो और अपने अनुभव शेयर करते है। लेकिन, सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो कभी शेयर ना करें जिसके कारण आपकी नकारात्मक छवि प्रस्तुत हों। आप सोशल साइट पर आपकी हॉबी या पसंदीदा चीजों से जुड़ी फोटो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देते रहें कि कोई व्यक्ति किसी अश्लील तस्वीर या पोस्ट से आपको टैग तो नहीं कर रहा। इससे आपकी संगत और माहौल का अंदाजा लगाया जाएगा।

सोशल साइटों पर प्रोफेशनल दिखें

फेसबुक और लिंक्डइन पर आमतौर व्यक्ति की पहचान उसका फोटो देखकर ही की जाती हैं तो आप इसमें वही फोटो डाले जिसमें आप फार्मल लुक में हो। आपकी फुल शॉट तस्वीर से अच्छा है हेड शॉट वाली तस्वीर डालें, वो भी मुस्कराते हुए। आप प्रोफेशनली कैसे दिख रहे हैं, यह पता करने के लिए आप फोटोफीलर नाम की एक साइट पर अपनी फोटो अपलोड करें। इससे फोटो में आप आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं या नहीं, यह पता लग जाएगा।

इंटरनेट पर आप किस तरह से हो रहे प्रस्तुत

नौकरी के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया के दौरान या उससे पहले एक बार आप अपने नाम को गूगल पर सर्च करके देखे कि गूगल आपके नाम के बारें में क्या दिखाता है। नियोक्ता की नजर से आपकी अपने बारे में क्या राय बन रही है और संबंधित नौकरी के लिए आप खुद को हायर करेंगे या नहीं, इन सवालों का जवाब ढूंढें। जवाब 'न' में हो तो कारणों की सूची बनाएं। हो सकता है आपके पोस्ट गलत विचारधारा को प्रकट कर रहे हों या आपके दोस्त आपकी वॉल पर अनुचित तस्वीरें या अनुचित कमेंट डाल रहे हों। इसके लिए अपनी सेटिंग बदलें और दोस्तों से कहें कि वे ऐसी पोस्ट न डालें। नियोक्ता को आपकी प्रोफाइल कैसी दिख रही है, इसके लिए अपने फेसबुक पेज के ऊ पर दाएं कोने पर जाएं और प्रिव्यू माई प्रोफाइल पर जाकर देखें। आप चाहें तो अपने मुताबिक सेटिंग को एडिट भी कर सकते हैं। वैसे तो अधिकतर नियोक्ता उम्मीदवार को परखने के लिए उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाते हैं, पर कई बार क्षेत्र के हिसाब से भी दूसरी साइट पर आपकी मौजूदगी को भी परखते हैं। जैसे, अगर कोई डिजाइनर है तो उसकी पिनट्रेस्ट या टम्बलर प्रोफाइल को परखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति मॉडल है तो उसके इंस्टाग्राम को परखा जाता है, वहीं निजी पृष्ठभूमि को जानने के लिए कंपनी फेसबुक प्रोफाइल को देखना पसंद करती है।

ऐसा होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल

लिंक्डइन अपने करियर क्षेत्र और पेशे से जुड़े पेशेवर लोगों से नेटवर्क बनाने का अच्छा जरिया है। अपने करियर क्षेत्र से संबंधित ग्रुप जॉइन करें। लिंक्डइन के मानदंडों के हिसाब से चलें। यदि आप चाहते हैं कि नियोक्ता, बॉस, या सहकर्मी आपके निजी ब्लॉग या पोस्ट को न देख पाएं तो इसके लिए सेटिंग पर जा कर लिंक्डइन प्रोफाइल में 'फीड' के सिंक ऑप्शन को अनचेक कर दें। लिंक्डइन पर डाले गए रेज्यूमे को बहुत से लोग देखते हैं। इसलिए जो सच है, वही लिखें। हाल की फोटो डालें। फॉर्मल ड्रेस में हेड शॉट डालें। अपने लिंक्डइन यूआरएल को छोटा रखें, जिससे गूगल पर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ढूंढना आसान हो। इसके लिए आप लॉगिन करें, अकाउंट और सेटिंग्स पर जाकर पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करें और पेज पर यूआरएल एडिट करने का विकल्प चुने।

यदि आप फेसबुक प्रोफाइल को पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने प्रोफाइल में जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है आपको कुछ कमेंट के साथ-साथ तस्वीरें हटानी होंगी, जो आपकी पेशेवर जिंदगी के लिहाज से ठीक न हों। अगर आपको पार्टी करना पसंद है और नहीं चाहते कि भावी बॉस आपकी पर्सनल प्रोफाइल देखें तो सारी प्राइवेसी सेटिंग में 'फ्रेंड्स ओनली' का ऑप्शन चुनें और कौन आपके प्रोफाइल को देखेगा, इसके प्रति सेलेक्टिव रहें। फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग बदलें, ताकि यह तय हो सके कि आपके पेज को कौन देखेगा। इससे नियोक्ता भी आपसे एड हुए बिना आपकी प्रोफाइल को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा सेटिंग में बदलाव करें, ताकि लोग आपकी फेसबुक वॉल पर कोई अनुचित पोस्ट न डाल सकें। अगर आपने कहीं काम किया है और उस संस्था से जुड़े लोग आपकी फ्रेंडलिस्ट में हैं तो कस्टम सेटिंग का विकल्प चुन कर उन्हें अपनी निजी पोस्ट देखने से रोक सकते हैं।

कम लागत से शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

स्टार्टअप शुरू करने में थोड़ी इनवेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कई लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके तो आप जरूर करना चाहेंगे। यहां हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक लाख रुपए से कम लागत में भी शुरू किए जा सकते हैं।

आजकल स्टार्टअप का जमाना है। हर कोई नौकरी की बजाए अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है। स्टार्टअप शुरू करने में थोड़ी इनवेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कई लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके तो आप जरूर करना चाहेंगे। यहां हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक लाख रुपए से कम लागत में भी शुरू किए जा सकते हैं। हम यहां जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें महज 50,000 रुपए की लागत से शुरू किया जा सकता है। इनवेस्टमेंट के हिसाब से इन कामों को बढ़ाया भी जा सकता है।

पुरानी कारों की डीलरशिप

भारत में कारों का बिजनेस खूब बढ़ रहा है ऐसे में नई कारों की डीलरशिप के साथ-साथ सेकंड हैंड कारों का बाजार भी डिमांड में है। आप पुरानी कारों की डीलरशिप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डीलरशिप के अलावा इसमें आप कमिशन भी कुछ कमा सकते हैं। बशर्ते आप को क्लांइट को ढूंढ़ना होगा और उनको डील करानी होगी।

आइस क्रीम पार्लर

आइस क्रीम पार्लर भी एक बढ़िया निवेश है। सर्दियों के मौसम को छोड़ दें तो ये हमेशा मांग में रहता है। इसके लिए आपको बस एक फ्रीजर खरीदना होता है या फिर आप आइसक्रीम कंपनियों की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इनमें क्वालिटी वडीलाल जैसी बड़ी आइसक्रीम कंपनियां शामिल हैं और ये कंपनियां आइसक्रीम बिक्री का 10-20 फीसदी तक कमीशन के रुप में देती हैं।

ड्राइविंग स्कूल

ड्राइविंग स्कूल शुरू करना एक बेहतरीन आयडिया है और देश में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं रहने वाला। शहरों में तो आजकल एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ड्राइविंग नहीं सीखना चाहता हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक गाड़ी की जरुरत पड़ती है जो कि आप सेकेण्ड हैंड भी खरीद सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कुछ ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले लोग एक दिन में 8 से 10 हजार रुपए तक कम लेते हैं। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है या फिर आप किसी दूसरे आदमी से भी क्लासेज दिलवा सकते हैं।

मोबाइल गैरेज

शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कारों की संख्या में तेजी से बढ़ात्तरी हो रही है। आम वाहनों की तरह कार में भी खराबी आना आम समस्या है। ऐसे में कार के मालिक को जरूरत होती कि कार जहां खड़ी है वहीं पर कोई मैकेनिक आकर कार रिपेयर कर जाए। ऐसे में यदि आप कार- ऑटो रिपेरिंग का थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं तो लोगों को मोबाइल गैरेज की सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है एक सेकंड हैंड बाइक और एक टूल बॉक्स जोकि दोनों में 50 हजार तक में आ जाएंगे। अपने साथ आप एक हेल्पर या मैकेनिक रखें तो बेहतर होगा। मोबाइल गैरेज के जरिए आप 2 से 5 हजार रुपए तक रोज कमा सकते हैं।

एजुकेशन लोन डिफॉल्ट छात्रों का क्रेडिट स्कोर हो सकता है खराब

सब्सिडी या कम ब्याज पर दिए गए एजुकेशन लोन में बढ़ रहे डिफाल्ट के मामलों के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल कहा कि इस तरह की डिफॉल्ट हिस्ट्री छात्रों के क्रेडिट स्कोर पर विपरीत असर डाल सकती हैं जो कि उनकी ओर से भविष्य में लिए जाने वाले किसी अन्य लोन में मुसीबतें पैदा करेगा।

कम राशि में डिफॉल्ट के मामले ज्यादा

सिबिल ने बताया कि एजुकेशन लोन पर इस तरह के डिफॉल्ट मामले करीब 5 फीसदी हैं, जिनमें 90 दिनों से ज्यादा का ड्यूज है। कम ब्याज दरों पर 4 लाख से कम राशि के लोन के डिफॉल्ट के मामले (8.1 फीसदी) लंबी राशि के लोन के मुकाबले ज्यादा हैं। अन्य श्रेणियों के लिए तुलनात्मक डिफॉल्ट दरें हैं, 4 से 5 लाख के लिए 48 फीसदी और 5 से 15 लाख के लिए 2.1 फीसदी। वहीं 15 लाख के ऊपर की राशि के बड़े लोन पर डिफॉल्ट के मामले करीब 1 फीसदी हैं।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर

आपका क्रेडिट स्कोर दरअसल आपकी ओर से पूर्व में लिए गए लोन और उसके चुकाने का ब्योरा भर होता है। बैंक आपके लोन की अर्जी को आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद ही मंजूर करता है। अगर, अपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो बैंक आपको आसानी से लोन मुहैया करा देते हैं।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर और इसे कौन देता है

क्रेडिट स्कोर तीन अंको की एक संख्या होती है, जो 300 से 900 के बीच होती है। क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होता है, उसे उतना ही बेहतर माना जाता है। एक डिफॉल्ट करने पर भी क्रेडिट स्कोर कमजोर हो सकता है। 79 फीसदी व्यक्तिगत लोन 750 से ज्यादा के स्कोर पर ही अप्रूव किए जाते हैं। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड क्रेडिट स्कोर देता है।

घर बैठे चेक करें अपना क्रेडिट स्कोर

आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए। यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। आपको शुल्क के रूप में 470 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद ऑथेन्टिकेशन के लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से कम से कम तीन सवालों के सही जवाब आपको देने ही होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस की दूसरी गारंटी, फ्री में होगा 25 लाख तक का इलाज

नईदिल्ली। कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना स्कीम लॉन्च की। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता में आने पर 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा करती है। यह दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस की दूसरी गारंटी है। इससे पहले 6 जनवरी को कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना नाम से एक योजना लॉन्च की थी। उस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा की गई थी। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो दोनों योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया जाएगा। लॉन्च के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए जीवन रक्षा योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जीवन रक्षा योजना राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तरह ही काम करेगी।

मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नईदिल्ली। फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जजों के वेतन में परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस गवई की बेंच ने राज्य सरकारों पर टिप्पणी की है। चुनावी वादों के लिए सरकारों के पास पैसा है लेकिन जजों को सैलरी देने में परेशानी हो रही है। फ्री बीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मुफ्त की योजनाओं की बहार आई हुई है और दिल्ली चुनाव में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से अपने अपने वादे और दावे किए हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी मायने रखती है और जजों को सैलरी देने में परेशानी की बात कही गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी बिजली-पानी मुफ्त की बात लगातार कही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के वेतन में परेशानी आ रही है। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है।

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 जनवरी को होगी

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की 10 जनवरी को बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच जोरदार चुनावी लड़ाई के लिए मंच पूरी तरह तैयार है। जबकि दिल्ली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपनी चुनावी जमीन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा अपने नारे परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने और शराब नीति मामले सहित घोटाले के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के खिलाफ एक लक्षित अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के बाद दो दशकों से अधिक समय तक दिल्ली में सत्ता में वापस आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मीडिया के साथ सीएम आवास पहुंचे संजय सिंह और सौरभ

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार को उस समय गतिरोध पैदा हो गया जब पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से रोक दिया। आप नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक नवीकरण खर्च के भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए एक मीडिया दौरे की योजना बनाई थी। प्रवेश से इनकार किए जाने के बाद आप नेताओं की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई और उन्होंने 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के बाहर धरना दिया। पुलिस ने प्रवेश की अनुमति की कमी का हवाला दिया, और भारद्वाज ने जवाब दिया कि एक मंत्री और सांसद को मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता क्यों है। आप नेताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन की तैनाती के साथ बैरिकेड्स लगाए गए थे।

एक देश, एक चुनाव का संजय राउत ने किया विरोध

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक ही पार्टी और नेता के तहत एक समेकित राजनीतिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पर दलबदल कराने की कोशिश कराने का आरोप लगाया है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संजय राउत ने कहा कि एक देश, एक चुनाव विधेयक से एक पार्टी, एक चुनाव और एक नेता, एक चुनाव को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में विपक्ष सक्रिय रूप से भाग लेगा। विधेयक जेपीसी को भेज दिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि जेपीसी का प्रयास विधेयक की निष्पक्ष जांच करना होगा।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले एस जयशंकर

पीएम मोदी ने देश को 'चलता है' से 'होगा कैसे नहीं' की सोच में बदला

भुवनेश्वर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया। तीन दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान देश और विदेश से पांच हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई। सम्मेलन का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया।

इस दौरान 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 'चलता है ' से 'होगा कैसे नहीं ' वाली सोच में बदल दिया है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के विकास में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा पीढ़ी पर प्रभाव को समझाते हुए विदेश मंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का उदाहरण दिया।

विदेश मंत्री ने कहा कि 'एक बार पीवी सिंधु ने बताया था कि पीएम मोदी युवाओं के लिए आदर्श क्यों हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने देश को 'चलता है' वाले रवैये से 'बदल सकता है' और फिर 'होगा कैसे नहीं' वाली सोच में बदल दिया है।' विदेश मंत्री ने कहा कि 'एआई, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, स्टार्टअप्स और खेलों से लेकर वैश्विक बदलाव में युवा पीढ़ी बड़े बदलाव ला रही है। खुद का विकास करना बेहद जटिल है, लेकिन जब हमें ये विश्वास है कि कुछ भी असंभव नहीं है तो इस सोच के चलते ये आसान हो गया है।' विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों से भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी से नियमित अंतराल पर भारत आने की अपील की, ताकि उनका भारत से जुड़ाव हो सके। प्रवासी भारतीय दिवस

सम्मेलन 8-10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है।

आज पीएम मोदी करेंगे शिरकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों हासिल करने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। वह सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगी। इस सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है।

ओडिशा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि ओडिशा सरकार 50 देशों के प्रवासी भारतीयों के सामने राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा, सम्मेलन का प्रत्येक प्रतिनिधि ओडिशा पर्यटन के राजदूत की भूमिका निभाएगा और हमें उम्मीद है कि राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत विभिन्न देशों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी।

महाराष्ट्र में मिली हार, हाईकोर्ट पहुंचे इंडिया ब्लॉक के कई उम्मीदवार

■ **अब तक 63 याचिकाएं दायर**

मुंबई। इंडिया गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विसंगतियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों में लगभग 63 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ याचिकाएँ पहले दायर की गई थीं, लेकिन कई मंगलवार को दायर की गईं, क्योंकि कानून द्वारा निर्धारित 45 दिन की निर्धारित अवधि जिसके भीतर चुनाव याचिकाएँ दायर की जानी चाहिए, 7 जनवरी को समाप्त हो गई। चुनाव याचिकाएँ प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा स्वयं दायर की जानी चाहिए। खबर है कि करीब 25 कांग्रेस नेताओं ने याचिका दायर की है,

जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र के संग्राम थोपटे, रमेश बागवे और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेता शामिल हैं।

विदर्भ के आठ कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुदादे, यशोनती ठाकुर, सुभाष धोटे, गिरीश पांडव, शेखर शेंडे, सतीश वरजुरकर, और संतोष सिंह रावत साथ ही उत्तरी महाराष्ट्र के चार नेता - केसी पडवी, बालासाहेब थोराट, कुणाल पाटिल और प्रवीण चावरे - उच्च न्यायालय की नागपुर और औरंगाबाद पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। मराठवाड़ा के पांच कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव याचिका दायर की है। कुछ अन्य याचिकाएं राकांपा (सपा) और शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवारों द्वारा वकील असीम सरोदे के माध्यम से प्रधान पीठ में दायर की गई हैं। इन राजनीतिक उम्मीदवारों में मनोहर कृष्ण माधवी, प्रशांत सुदाम जगताप, महेश कोठे, नरेश रतन मनेरा और सुनील चंद्रकांत भुसारा शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव में कदाचार का आरोप लगाया है, जिसमें डुप्लिकेट वोटिंग, छुपाए गए आपराधिक मामले, संपत्ति छिपाना, ईवीएम में खराबी, रिश्वतखोरी और चुनाव पारदर्शिता की कमी शामिल है। पुणे में हडपसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राकांपा (सपा) के उम्मीदवार जगताप ने राकांपा (अजित पवार गुट) के उम्मीदवार चेतन विट्ठल तुपे की चुनावी जीत को चुनौती दी है। जगताप की याचिका में दावा किया गया है कि तुपे ने जानबूझकर अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को छुपाया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 ए का उल्लंघन करते हुए अपनी आय के विवरण का खुलासा करने में विफल रहे।

दिल्ली चुनाव में आप को ममता का मिला समर्थन

नईदिल्ली। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को समर्थन देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने पार्टी का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आप को समर्थन देने का ऐलान किया है. मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूं।% धन्यवाद दीदी. आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा समर्थन और आशीर्वाद दिया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती तीन दिन बाद आठ फरवरी को की जाएगी। आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद मंगलवार को उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में काम की राजनीति और गाली-गलौज की राजनीति के बीच मुकाबला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव की तारीख़ का एलान हो चुका है। सभी कार्यकर्ता पूरी ताक़त और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जुनून के आगे इनके बड़े-बड़े तंत्र फ़ेल हो जाते हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी ताक़त हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव काम की राजनीति और गाली-गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति के साथ ही होगा। हम ज़रूर जीतेंगे।

शीशमहल की हकीकत जनता के सामने आ रही: भाजपा

नईदिल्ली। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के इस्मारक की हकीकत तार-तार होकर जनता के सामने आती जा रही है। आज जिस प्रकार का प्रदर्शन आप के नेता सदन व एक मंत्री के द्वारा हुआ, वे जितना भी प्रयास कर लें परंतु शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की विलासिता का स्मारक है उसे बचा नहीं सकते। आप का नेचुरल कैरेक्टर है हमेशा अराजकता पैदा करना और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। अरविंद केजरीवाल भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारे काटी थीं जो उनकी अराजक प्रवृत्ति का सबूत है। मार्च 2014 को भाजपा के कार्यालय पर हमला किया गया था जिसमें इनकी (आप) सेंट्रल कमिटी बोर्ड के मुख्य लोग थे... अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आप चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार क्यों कर रहे थे? ये लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता समझती है।

दिल्ली में आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक (शीश महल) की हकीकत जनता के सामने आती जा रही है। आज एक भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा किया गया। ये जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल की विलासिता का स्मारक है, उसे बचा नहीं सकते। ये लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भलीभांति समझती है।

खेल
प्रमुख समाचार

शादी के बाद एक बार फिर एक्शन में दिखेंगी पीवी सिंधु

नईदिल्ली। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अपने 2025 सीजन की शुरुआत योनेक्स-सनराइज इंडिया ओपन से करेंगी। इंडिया ओपन सुपर 750 के तीसरे संस्करण की शुरुआत 14 जनवरी से इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में होगी, जहां पर विश्वभर के खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पिछले साल शादी के बंधन में बंधने वाली सिंधु इस बार सुपर 750 के टूर्नामेंट में वुमेंस सिंगल्स में खेलते हुए नजर आ सकती हैं। पीवी सिंधु ने अंतिम बार सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में शिरकत किया था, जहां उन्होंने चाइना की लुओ यू वू को सीधे सेंटो में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

सुपर 750 भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित मुख्य प्रतियोगिता रही है, टूर्नामेंट के इस सीरीज में ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन, एन से यंग और विश्व नंबर एक खिलाड़ी शि यूकी मैदान में फैंस के बीच अपना जलवा बिखेरते हुए जर आएंगे, ये टूर्नामेंट शुरुआत से से [illegible] विश्व टूर का हिस्सा रहा है, जहां पर विजेता को 9,50,000 यूएस डॉलर की धनराशि और 11000 पॉइंट्स मिलते हैं, टूर्नामेंट के तीसरे सीजन में मेजबान भारत की ओर से 21 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से 21 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत के लिए मेंस सिगल्स में 3, विमेंस सिंगल्स में 4, मेंस डबल्स में 2, विमेंस डबल्स में 8 और मिक्स्ड डबल्स में 4 खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, पिछले दो सीजनों में भारत की ओर से 14 खिलाड़ियों ने प्रवेश किया था। इस सीजन में मेंस डबल्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एचएस प्रणय पर सभी की निगाहें होंगी। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पिछली बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी, वहीं प्रणॉय का सफर अंतिम चार में थम गया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में निचले स्तरों से 600 से ज्यादा अंकों की रिकवरी

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार (8 जनवरी) को दिन की बड़ी गिरावट से उबरते हुए लगभग सपाट बंद हुए। कारोबार के अंतिम दो घंटों में घाटे को कम करने से पहले सेशन के दौरान दोनों बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.8% गिर गए थे। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार (8 जनवरी) को 78,319 अंक पर खुला। खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर यह लाल निशान में फिसल गया। कारोबार के दौरान यह 700 से ज्यादा अंक लुढ़क गया था। अंत में सेंसेक्स 50.62 अंक या 0.06% गिरकर 78,148.49 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी पॉजिटिव शुरुआत के साथ खुला। मगर खुलने के कुछ ही देर में यह गिरावट में चला गया। यह 23,496 अंक के लेवल तक गिर गया था। अंत में निफ्टी 18.95 अंक या 0.08% की मामूली गिरावट लेकर 23,688.95 पर लगभग सपाट सेटल हुआ।

टैक्स फाइलिंग नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार

नईदिल्ली। आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और कम झंझटभरा बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पिछले एक दशक में 120 अरब डॉलर से अधिक के विवाद बढ़ने के कारण इसे सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और इसे जनवरी के मध्य तक सार्वजनिक परामर्श के लिए पेश किया जा सकता है। इसके बाद संशोधित कानून को सरकार के आगामी फरवरी के बजट में शामिल किए जाने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और विवादों को कम करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है। सरकार कर कानूनों को आसान और समझने में सरल बनाने के लिए बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

स्विगी और जेप्टो को चुनौती देने उतरा जोमैटो

नईदिल्ली। क्या आप भूख लगते ही कुछ ही मिनटों में खाना पाने की उम्मीद रखते हैं? ज़ोमैटो ने इस इच्छा को हकीकत में बदलने का कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी 15 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर दी है, जिससे क्विक फूड डिलीवरी सेगमेंट में हलचल मच गई है। यह नई सुविधा ज़ोमैटो ऐप पर चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और फिलहाल मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के कुछ इलाकों में ही लाइव है। ऐप के 15 मिनट डिलीवरी टैब में ऐसे व्यंजन पेश किए जा रहे हैं जो या तो रेडी-टू-ईट हैं या जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। ज़ोमैटो ने इस सेवा को तेज और सटीक बनाने के लिए रेस्त्रां को 2 किलोमीटर की सीमा तक सीमित कर दिया है। ज़ोमैटो का यह कदम स्विग्गी के 'बोल्ट', मैजिकपिन और जेप्टो जैसी सेवाओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। हालांकि इस सेवा की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

व्हाइटओक कैपिटल एमएफ की नई स्कीम में मौका!

नईदिल्ली। एसेट मेनेजमेंट कंपनी व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने अपनी नई स्कीम व्हाइटओक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड उतारी है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो सेक्टरल/थीमेटिक कैटेगरी में आती है। स्कीम का मकसद लंबी अव धि में कैपिटल एप्रिसिएशन जेनरेट करना है। यह न्यू फंड ऑफर 8 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। म्युचुअल फंड हाउस का कहना है कि यह एनएफओ एक क्वालिटी फैक्टर थीम पर आधारित डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा, जिसमें मजबूत फंडामेंटल और सस्टेनेबल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाली कंपनियों को शामिल किया जाएगा। यह स्कीम मुख्य रूप से इक्विटी निवेश पर फोकस्ड होगी, लेकिन इसमें एक तय सीमा में डेट और REITs/InVITs में भी निवेश किया जाएगा।

राजनीति को किनारे रखकर बनानी होगी भविष्य की योजना

शंकर अय्यर

मार्क ट्वेन ने कहा था कि इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन यह मिलता-जुलता तो प्रतीत होता ही है। 1929 से लेकर 2007 तक दुनिया ने तमाम वित्तीय झटकों और अनिश्चितताओं का अनुभव किया। मजे की बात है कि हर संकट एक जैसा लगता था, लेकिन वे अलग थे और उनके समाधान भी अलग-अलग तरीके से तैयार किए गए थे। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया भर के देश आशंकित हैं। मुद्राएं लुढ़क गई हैं। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता का दौर चल रहा है। दरअसल, बाजारों में मची यह उथल-पुथल इस बात पर अनिश्चितता का प्रतीक है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद क्या करने वाले हैं?

वैश्विक कहानी से परे भारत की समस्याएं काफी हद तक भारतीय प्रकृति की हैं। भारत एक बार फिर उस दोराहे पर आ खड़ा हुआ है, जहां उसे राजनीति को किनारे रखकर भविष्य की योजना बनानी होगी। हाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट को एक बार का विपथन मान कर नजरअंदाज किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि मांग में कमी जरूर आई है, लेकिन बाजार के आकार को लेकर कोई संदेह नहीं है। बीते नवंबर तक भारतीयों ने हर घंटे 500 से ज्यादा कारें और 2,000 दोपहिया वाहन खरीदे। इसी अवधि में भारतीय करीब सात करोड़ मोबाइल फोन खरीद चुके हैं, जिसके साल के अंत तक 15 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इस साल भारत में करीब 800 टन सोना आयात होने की भी उम्मीद है।

स्पष्ट है कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना तभी कर सकता है, जब वह अपनी विशाल आबादी का लाभ उठाए और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता यही है कि देश में असमानता बढ़ी है और राजनीतिक वर्ग भी इससे भली-भांति परिचित है। मनरेगा पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत से महिलाओं को नकद लाभ हस्तांतरण, ये सभी संकट के संकेत हैं। दरअसल, अभी कुछ ही समय पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की सब्सिडी के 4.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने को लेकर आगाह भी किया था। देश में मौजूदा मंदी काफी हद तक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का ही

प्रभाव है। खराब रिटर्न की वजह से कृषि घरेलू आय 12 हजार रुपये प्रतिमाह बनी हुई है और उपलब्धता भी प्रभावित हुई है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं की मांग व खपत पर भी असर पड़ा है।

1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हर चीज इंतजार कर सकती है, पर खेती नहीं। लेकिन तथ्य यह है कि पिछले सात दशकों में राजनीतिक दलों ने कृषि को राजनीतिक दान का मामला बना दिया है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगा देश का 54 फीसदी से ज्यादा कार्यबल जीवीए के 18 फीसदी पर निर्भर है और यही वह मूल कारण है, जिसकी वजह से गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती। जाहिर है कि भारत को अपनी कृषि को स्वतंत्र व आधुनिक बनाने की जरूरत है।

2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का रोडमैप पेश किया, जिसमें उन्होंने अंतरालों, अवसरों व चुनौतियों की बात की। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयास पर भी निर्भर थी। लेकिन 13 राज्यों की सरकारें पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाईं। एनटी रामा राव ने 1980 के दशक में जिस राजनीतिक और आर्थिक तथ्य पर प्रकाश डाला वह यह था कि भारत का हर इंच राज्यों द्वारा शासित है। केंद्र के प्रत्येक कार्यक्रम को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाना होता है। लेकिन संसदीय समितियों की रिपोर्ट वाटरशेड प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कृषि प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना को आगे बढ़ाने, प्लास्टिक पार्क योजना के तहत विनिर्माण नौकरियों के सृजन और प्रशिक्षुओं को बढ़ावा देने में राज्यों के खराब प्रदर्शन का खुलासा करती है।

बालोद में सीएम साय का बड़ा ऐलान

किसानों को एकमुश्त मिलेगी अंतर की राशि

रायपुर। जिले के मां बंजारी मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए. जहां सीएम साय ने 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के अंतर का राशि एकमुश्त देने की बात कही है.हितग्राही सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार को एक साल पूरा हुआ है और एक साल में मोदी की गारंटी का काम सांय सांय हुआ है. सभी वादे पूरा किए जा रहे हैं. 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरा किया गया है. 8 लाख 46 हजार की स्वीकृति केंद्र से आ गई है.

10 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं. 3 लाख से अधिक आवास फिर से मिलने जा रहा है. पिछले साल बालोद से ही किसानों के अंतर का राशि हस्तांतरित की गई थी. इस साल धान खरीदी का लक्ष्य और बढ़ेगा.धान खरीदी बंद होने के साथ ही रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा. अंतर की राशि भी एकमुश्त भेजी जाएगी = विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सीएम ने दिया 115 विकास कार्यों की सौगात = मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यहां हमने 115 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन किया है. इससे विकास की गंगा बहेगी. मटिया मोती बांध के लाइनिंग कार्य का भी भूमिपूजन किया है. इसके बाद सुगमता से किसानों के खेतों में पानी पहुंच पाएगा. सीएम ने इस दौरान बालोद में नालंदा परिसर और 400 सीटर ऑडिटोरियम बनाने की भी घोषणा की है.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 141 करोड़ की सौगात मिल रही है. इसके लिए मैं बालोद वासियों को बधाई देता हूं. जब से राज्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से गांव गांव विकास के काम तेजी से हो रही है. उन्होंने कहा चुनाव के समय गारंटी का वादा किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं. देश में ये उदाहरण केवल भाजपा कर रही है. हर एक वादा पूरा कर रही है.

हम बिना भेदभाव के हम काम दे रहे हैं. कोई भेदभाव नहीं है. भाजपा ने बालोद जिले के निर्माण किया था तो संवारने की जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार की ही है।

समारोह में मौजूद कांकेर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम साहब ने जो काम किया है, वो काबिल के तारीफ हैं. मैं उनको नमन करता हूं. बालोद एक धर्म नगरी हैं और यहां उन्होंने करोड़ों रुपए का सौगात दिए हैं. उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. इस दौरान भोजराज नाग ने कुछ नए विकास कार्यों की मांग सीएम साय के समक्ष रखी.सीएम साय ने नवीन भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और सांसद भोजराज नाग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे।

बाबू भैया की कलम से ✍

मुकेश हत्याकांड की जांच तय करेगी पत्रकारिता का भविष्य

पत्रकारिता की बेदी पर एक और कर्मठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बली चढ़ गई। गहन नक्सल क्षेत्र बीजापुर में सार्थक पत्रकारिता को अंजाम देते नवजवान पत्रकार की एक रसूखदार ठेकेदार ने नृसंश हत्या कर लाश को अपने ही बाड़े में स्थित सेफ्टी टैंक में दफना दिया गया। जिस क्रूरता से मारा गया वह दिल दहला देने वाला प्रसंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर व सर पर गहरी चोट के 15 निशान मिले हैं। बर्बरता की हद तो ये है कि पेट में लीवर के 4 टुकड़े गर्दन की हड्डी और पांच पसलियां टूटी मिली। साथ ही उसका दिल भी फटा हुआ मिला है। पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने उनके 12 सालों के कार्यकाल में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। यहीं तक क्रूरता नहीं उससे भी बढ़ कर लाश को ठेकेदार के अवैध कब्जे पर बने कैम्पस में स्थित सेप्टिक टैंक में डाल कर ऊपर से सीमेंट से उसे चुन दिया गया। सोचिये समाज में अपने आप को समाजसेवी के रूप में अपने पैसे के दम पर प्रचारित करने वाले उस ठेकेदार का दिमाग कितना क्रिमिनल है। जिस सड़क निर्माण की गड़बड़ी की रिपोर्टिंग इस नवजवान पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने की थी, उस सड़क निर्माण में 120 करोड़ की हेराफेरी में अधिकांश राशि काम अधूरा रहने के बाद भी भुगतान हो जाना। हत्या करने की निडरता के साथ योजना को अपने ही घर पर बनाना। उसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाना। इस बात की ओर संकेत देती है कि संबंधित ठेकेदार की सिस्टम में कितनी गहरी पैठ रही होगी। दो दिन की गुमसुदगी के बाद भी पुलिस द्वारा खास तवज्जो ना देना। सेप्टिक टैंक के पास अंतिम मोबाइल लोकेशन ट्रेस होना। वह भी पत्रकारों द्वारा ट्रेस किया जाना। पुलिस के अधिकारियों को शंका जाहिर करते हुए पत्रकारों द्वारा सेफ्टी टैंक की खुदाई करने के आग्रह के बाद भी पुलिस की ना नुकुर। दबाव बनाने के बाद खुदाई करना। पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकेश के भाई से अजब गजब अंदाज में बात करना,अनेक संदेह को जन्म दे रहा था। अंततः खुदाई हुई और पत्रकारों के संदेह की पुष्टि हुई। मुकेश का शव बुरी हालात में उसी सेफ्टी टैंक से निकला, जिसको तोड़ने के लिए पुलिस ना नुकुर कर रही थी। पुलिस ने तीन संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूरी कहानी का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि हत्या 1 जनवरी को देर रात ठेकेदार के बैडमिंटन कोर्ट वाले बाड़े में की गई। पुलिस के अनुसार हत्या की घटना को रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने अंजाम दिया था। लाश को ठिकाने लगाने का काम दिनेश चंद्राकर ने किया था। यह भी बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को भी थी। पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया है। ठेकेदार और उसके भाइयों की संलिप्तता का पता चलते ही प्रशासन ने ठेकेदार के 5 एकड़ जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन यार्ड के कब्जे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम भी किया है। दूसरे कब्जों को भी चिन्हांकित करके उस पर भी कार्यवाही की बात भी कही गई है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर फरार हो गया था। एसआईटी के प्रयासों से उसे हैदराबाद से गिरफ्तार करना बताया गया है। चारों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इधर इस मामले में जबरदस्त राजनीति भी होने लगी। अपनी सरकार पर आंच आते देख भाजपा सरकार की ओर से गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर यह आरोपित किया कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का पदाधिकारी था। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज से उसके करीबी रिश्ते थे। इसके साथ ही उन्होंने नियुक्ति पत्र के कुछ कागजात भी सबूत के तौर पर पत्रकारों को दिखाए। यह साबित करने का प्रयास भी किया गया कि सुरेश चंद्राकर पदाधिकारी था। आरोप का दीपक बैज ने तत्काल खंडन भी कर दिया था। कहा था कि जो घटना को अंजाम देता है वह पहले अपराधी है। विजय शर्मा ने यह कहते हुए भी कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक हमला किया कि बलौदा बाजार की घटना,सूरजपुर घटना, और बालोद समेत कई बड़ी घटनाओं में कांग्रेस के नेता ही हर अपराध में क्यों संलिप्त पाए जा रहे हैं। सफाई देते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैं यह नहीं कहता कि हर कांग्रेसी अपराधी है, लेकिन प्रत्येक बड़े अपराध के पीछे कांग्रेस के नेता ही क्यों निकल रहे हैं। जेल जा रहे हैं।

पत्रकार की नृशंस हत्या के मामले को देश के पत्रकार जगत ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है। यह इससे भी साबित होता है कि ना सिर्फ प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक में प्रदर्शन हुए बल्कि देश की पत्रकारों की दिल्ली के बड़े संगठन गिल्ड व प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी प्रदर्शन किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सरकार से कड़ी कार्यवाही करने को दबाव बनाया। यह भी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने में तत्परता दिखाई है। उससे कुछ हद तक संतोष हुआ ,लेकिन अनेक प्रश्न अब भी खड़े हुए है। एसआईटी में स्थानीय अधिकारियों को रखना उस बीजापुर के थानेदार को भी रखना जिस पर स्थानीय पत्रकारों ने शंका जाहिर की है। रायपुर मुख्यालय से किसी को रखे जाने की मांग पर विचार नहीं किया जाना। पुलिस अधीक्षक पर भी पत्रकारों ने शंका जाहिर की है। उसे वहां से ना हटाया जाना। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में यदि पत्रकारों को व मृतक पत्रकार के परिवार को सही न्याय नहीं मिला। पिछली घटनाओं की तरह इसका भी अंजाम हुआ। मुख्य आरोपी अगर बच निकला तो यह भविष्य की पत्रकारिता के लिए काला समय आने का संकेत होगा।

कार्यों में लेट लतीफी व लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : केदार कश्यप

जल संसाधन मंत्री ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की

रायपुर । जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही निविदा की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय-सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

बैठक में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए, साथ ही उन्होंने समय-समय पर कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।

मंत्री कश्यप ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु ईओआई बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें।बैठक में मंत्री कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री से महाप्रबंधक रेलवे ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बिलासपुर के चकरभाटा में चालीहो महोत्सव में होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री साय 9 जनवरी को बिलासपुर के चकरभाटा में चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से अपरान्ह 2.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.10 बजे बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, चकरभाटा, बिलासपुर पहुंचेंगे और सिन्धू अमरधाम आश्रम, झूलेलाल नगर में आयोजित चालीहो महोत्सव में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी: बैज

रायपुर। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही वह दावा किया था कि नया धर्म स्वातंत्र विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है, 60 दिन के भीतर लागू हो जायेगा, लेकिन 1 साल बीतने के बाद आज तक मौन है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश के शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी है। भाजपा खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देती है फिर वर्ग संघर्ष करवाती है विपक्ष में रहते हुये धर्मांतरण के नाम पर फसाद करने वाले भाजपाई पिछले एक साल से प्रदेश में होने वाली धर्मांतरण की घटनाओं पर चुप्पी साध लिये है। यही नहीं खबरें तो यह भी आ रही है कि धर्मांतरण कराने वालों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला हुआ है। जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं के बाद भाजपा की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि इन घटनाओं को उसका समर्थन है।जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिये बड़ी समस्या बताया था, तथा कानून बनाने के लिये केन्द्र से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केन्द्र में बैठी मोदी सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है।

अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के नियंत्रण से बाहर: शुक्ला

रायपुर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और वित्तीय कुप्रबंधन के चलते देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उल्टे पांव भाग रही है। वर्तमान में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत की तुलना में बेहद कम, मात्र 6.4 प्रतिशत है। सरकार के अनुमान से कम वृद्धि दर का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया और अब हस्स्का यह अनुमान वित्त मंत्रालय के अनुमान से भी बेहद कम है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, आज 10 साल से अधिक हो गए केंद्र की सरकार में आए, महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन यह सरकार जनता के प्रति अपने जवाबदेही से भाग रही है। भुखमरी इंडेक्स में देश को लगातार निचले पायदान पर धकेला जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल कर 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया है। मोदी राज में देश पर कुल कर्ज का भार 2014 की तुलना में तीन गुना अधिक हो चुका है।

गौठान बंद करके गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार गौठानों को बंद करके गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है। भाजपा सरकार के 1 साल में 10000 से अधिक गौवंशी पशुओं की तस्करी हुई है। कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा ने गौठानों का विरोध किया था, आज उनकी मंशा स्पष्ट समझ में आ रही है कि वह तस्करों को मदद करने के लिए गायों के संरक्षण के लिए बनाए गए गोठान का विरोध कर रहे थे और सरकार बनते ही पहला कदम उन्होंने गोठानों को बंद किया है जिसके चलते पूरे प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ी है गौवंशों की सड़क पर दुर्घटना और भूख से मौत हो रही है और गौ माता के नाम से राजनीति करने वाले भाजपा आंख मूंदे बैठी हुई है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 साल से गोठाने बंद है सरकार उसे चालू करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि गौठानों को तत्काल चालू किया जाए और पूर्व की तरह ही वहां से चलने वाली योजनाओं को भी शुरू किया जाए। जिससे गौ तस्करी पर रोक लगे और गौ वंशों की सड़क दुर्घटना और अन्य कारणों से होने वाली मौत पर भी विराम लगे। भाजपा की सरकार ने गौ अभ्यारण बनाने का जो सपना दिखाया था।

पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नाम भाजपा सरकार का धोखा: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी किसान सरकार को ओबीसी विरोधी करार देते हुए कहा है कि इस सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में जो षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है उसके परिणाम सामने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पांचों के आरक्षण में ओबीसी के हक और अधिकारों में बड़ी डकैती इस सरकार ने की है। उदाहरण के तौर पर बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में जिला पंचायत सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के चार जनपद पंचायत में दो जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति महिला, एक अनारक्षित महिला और एक जनपद अध्यक्ष का पद अनारक्षित मुक्त रखा गया है। भाजपा के तमाम नेता होल्डिंग और विज्ञापन बोर्ड में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा कर रहे थे, आज आरक्षण प्रक्रिया के परीणाम सामने आने पर पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का ढोंग करने वाले भाजपाई दलिय चाटुकारिता में मौन है।

जिपं क्षेत्रों एवं जपं के अध्यक्षों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न

बिलासपुर। आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत बिल्हा, तखतपुर, कोटा एवं मस्तूरी के आरक्षण की कार्यवाही विहित प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी द्वारा किया गया । जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल भी मौजूद थे । जिला पंचायत बिलासपुर में 17 जिला पंचायत क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए 4 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट एवं 9 अनारक्षित सीट है। उपरोक्त सीटों के आरक्षण हेतु वर्ष 2019-20 में विभिन्न प्रवर्गो हेतु आरक्षित सीटों के आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम में आरक्षित किये जाने हेतु शासन के निदेशानुसार वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति प्रवर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 2, 4, 11, 12 एवं 13 आरक्षित थे। जिसमें अनुसूचित जाति महिला हेतु 2, 4, एवं 12 आरक्षित थे। अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र क्रमांक 15 व 16 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसुचित जनजाति महिला हेतु आरक्षित थे। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 5, 9, 14 एवं 10 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 10 एवं 14 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित था। वर्ष 2024-25 में चक्रानुक्रम में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 12 अनुसूचित जाति मुक्त एवं 11 और 13 अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित किये गये हैं।

डिप्टी सीएम शर्मा ने की गृह विभाग की समीक्षा

नशे का कारोबार करने वालों की कुर्क होगी संपत्ति

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के अमर बलिदानी स्मारक का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।बैठक में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया।

बिल्हा से धान खपाने टिकारी ले जा रहे दो ट्रैक्टर पकड़ाए, वाहन सहित 224 बोरी धान जब्त

बिलासपुर। धान के अवैध संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। मस्तुरी तहसील के ग्राम वेद परसदा में धान ले जाते दो ट्रैक्टर पकड़ाए। दोनों में 224 बोरी धान ले जाया जा रहा था। धान की कीमत लगभग 2.78 लाख बताई गई है। राजस्व, खाद्य और मंडी के अफसरों की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। जाँच के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त धान बिल्हा से विक्रय हेतु ग्राम टिकारी तहसील मस्तुरी ले जाया जा रहा है। उपरोक्त धान के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज यथा-धान परिवहन हेतु अनुमति आदेश, मण्डी शुल्क, धान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मौके पर उपस्थित वाहन चालकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त धान के उपार्जन केन्द्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए वाहन एवं उसमें भण्डारित 224 कट्टी (बोरी) धान को तहसीलदार द्वारा जप्त करते हुए प्रकरण निर्मित कर मण्डी अधिनियम के तहत् नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जावेगी। उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों में धान व्यापारियों और कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान को खपाने संबंधी क्रिया-कलापों पर कडी निगरानी रखने एवं उन पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है।निर्देशों के परिपालन में जिले में राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन किये जाने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही जारी है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोचियों और दलाल किस्म के लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीम ने मजबूत सूचना तंत्र बना रखा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.